नवसर्जन संस्कृति

PRGI No. GJHIN/25/A2786

नवसर्जन संस्कृति

PUBLISHED HIINDI DAILY FROM AHMEDABAD

वर्ष : 01
अंक : 228
दि. 22.05.2026,
शुक्रवार
पाना : 04
किंमत : 00.50 पैसा

‘कॉकरोच जनता पार्टी’ का डिजिटल विस्फोट, अकाउंट ब्लॉक होने के बाद और तेज हुई चर्चा

नई दिल्ली/मुंबई। सोशल मीडिया की दुनिया में पिछले कुछ दिनों से सबसे ज्यादा चर्चा जिस नाम की हो रही है, वह है Cockroach Janata Party। महज कुछ दिनों में इंटरनेट पर उभरे इस व्यंग्यात्मक अभियान ने ऐसा डिजिटल तूफान खड़ा किया कि इसके फॉलोअर्स की संख्या देश के बड़े राजनीतिक दलों से भी आगे निकल गई। अब इस पूरे घटनाक्रम ने नया मोड़ तब ले लिया, जब पार्टी के संस्थापक अभिजीत दीपके ने दावा किया कि भारत में उनके एक्स (पूर्व ट्विटर) अकाउंट को ब्लॉक कर दिया गया है।

हालांकि एक्स अकाउंट पर रोक लगने के बावजूद इंस्टाग्राम पर इस अभियान की लोकप्रियता लगातार बढ़ती जा रही है। दावा किया जा रहा है कि छह दिनों के भीतर पार्टी के इंस्टाग्राम अकाउंट पर करीब डेढ़ करोड़ फॉलोअर्स जुड़ गए। इतनी तेज वृद्धि ने सोशल मीडिया विश्लेषकों को भी चौंका दिया है। इंटरनेट पर यह आंदोलन अब केवल एक मजाक या मीम तक सीमित नहीं रह गया, बल्कि यह युवाओं की नाराजगी, बेरोजगारी और व्यवस्था के प्रति असंतोष का प्रतीक बनता दिखाई दे रहा है।

इस पूरे विवाद की शुरुआत एक न्यायिक टिप्पणी के बाद हुई। हाल ही में Justice Surya Kant द्वारा एक सुनवाई के दौरान कथित रूप से बेरोजगार युवाओं को लेकर की गई टिप्पणी सोशल मीडिया पर वायरल हो गई। बाद में न्यायमूर्ति ने स्पष्ट किया कि उनका इशारा केवल फर्जी डिग्रीधारकों की ओर था, लेकिन तब तक इंटरनेट पर “कॉकरोच” शब्द एक बड़े व्यंग्यात्मक ट्रेंड में बदल चुका था।

इसके बाद कई सोशल मीडिया पेज और अकाउंट “कॉकरोच जनता पार्टी” के नाम से सामने आने लगे। इनमें सबसे तेजी से

लोकप्रिय हुआ अकाउंट अभिजीत दीपके से जुड़ा बताया जा रहा है। इंस्टाग्राम पर इस अकाउंट की लोकप्रियता इतनी तेजी से बढ़ी कि इसने स्थापित राजनीतिक दलों के डिजिटल प्रभाव को भी चुनौती दे दी।

रिपोर्ट्स के अनुसार, Bharatiya Janata Party के इंस्टाग्राम पर लगभग 88 लाख फॉलोअर्स हैं, जबकि Indian National Congress के करीब 1.33 करोड़ फॉलोअर्स बताए जाते हैं। ऐसे में “कॉकरोच जनता पार्टी” का कुछ ही दिनों में इन दोनों दलों से आगे निकल जाना सोशल मीडिया की ताकत और वायरल संस्कृति का बड़ा उदाहरण माना जा रहा है।

अभिजीत दीपके ने एक्स अकाउंट ब्लॉक होने के बाद प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि उन्हें पहले से ही इस कार्रवाई की आशंका थी। उनके अनुसार, जैसा उन्होंने सोचा था, वैसा ही हुआ। उन्होंने दावा किया कि एक्स की ओर से उन्हें बताया गया कि स्थानीय नियमों, कोर्ट के आदेश या कानूनी शिकायत के आधार पर भारत में अकाउंट पर रोक लगाई गई है। हालांकि अभी तक एक्स प्लेटफॉर्म की ओर से इस मामले में कोई आधिकारिक सार्वजनिक बयान जारी नहीं किया गया है।

डिजिटल विशेषज्ञों का मानना है कि सोशल मीडिया पर व्यंग्य और राजनीतिक कटाक्ष का प्रभाव लगातार बढ़ रहा है। विशेषकर युवाओं के बीच ऐसे अभियान तेजी से लोकप्रिय होते हैं, क्योंकि वे सीधे उनकी भावनाओं, निराशा और व्यवस्था के प्रति असंतोष को सरल और वायरल तरीके से व्यक्त करते हैं। “कॉकरोच जनता पार्टी” भी उसी प्रवृत्ति का हिस्सा मानी जा रही है।

कई राजनीतिक विश्लेषकों का कहना है कि यह घटना केवल सोशल मीडिया ट्रेंड नहीं है, बल्कि यह इस बात का संकेत भी है कि आज की युवा पीढ़ी पारंपरिक राजनीतिक संवाद से हटकर नए और व्यंग्यात्मक माध्यमों के जरिए अपनी बात सामने रखना चाहती है।

इस पूरे घटनाक्रम ने अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स की जवाबदेही और डिजिटल सेंसरशिप को लेकर भी बहस छेड़ दी है। कुछ लोग अकाउंट ब्लॉक होने को नियमों के तहत सामान्य प्रक्रिया बता रहे हैं, जबकि कुछ इसे ऑनलाइन अभिव्यक्ति पर दबाव के रूप में देख रहे हैं। विशेषज्ञ यह भी मानते हैं कि इंटरनेट पर वायरल होने वाले ऐसे आंदोलन अक्सर अचानक उभरते हैं और बहुत तेजी से जनसमर्थन हासिल कर लेते हैं, लेकिन उनकी वास्तविक सामाजिक और राजनीतिक स्थिरता समय के साथ ही तय होती है। फिलहाल इतना जरूर है कि “कॉकरोच जनता पार्टी” ने देश की डिजिटल राजनीति और सोशल मीडिया विमर्श में अपनी मजबूत मौजूदगी दर्ज करा दी है।

मणिपुर में हथियार तस्करी नेटवर्क पर बड़ा प्रहार, 67 हथियार बरामद; उग्रवादी संगठन से जुड़े चार गिरफ्तार

इंफाल। पूर्वोत्तर राज्य Manipur में सुरक्षा बलों ने एक बड़े संयुक्त अभियान के दौरान हथियार तस्करी और उग्रवादी नेटवर्क पर बड़ा प्रहार करते हुए भारी मात्रा में हथियार और सैन्य उपकरण बरामद किए हैं। इस कार्रवाई में प्रतिबंधित उग्रवादी संगठन UNLF (Pambei faction) से जुड़े चार संदिग्धों को गिरफ्तार किया गया है। अधिकारियों के मुताबिक, यह अभियान हाल के महीनों में हथियार तस्करी के खिलाफ सबसे बड़ी कार्रवाइयों में से एक माना जा रहा है।

सुरक्षा एजेंसियों के अनुसार, कार्रवाई के दौरान कुल 67 हथियारों के साथ बड़ी मात्रा में गोला-बारूद और सैन्य स्तर के उपकरण जब्त किए गए। इनमें अत्याधुनिक असॉल्ट राइफल, स्नाइपर राइफल, मोर्टार, आरपीजी लॉन्चर और एंटी-ड्रोन जैमर जैसे संवेदनशील उपकरण शामिल हैं।

मणिपुर पुलिस ने बताया कि उन्हें खुफिया सूचना मिली थी कि लामशांग थाना क्षेत्र के लामदेंग इलाके में लूटे गए हथियारों और गोला-बारूद की अवैध बिक्री की तैयारी चल रही है। सूचना के आधार पर बुधवार को विशेष अभियान शुरू किया गया, जिसमें पुलिस, Assam Rifles और Central Reserve Police Force की संयुक्त टीमों को लगाया गया।

कार्रवाई के दौरान सुरक्षाबलों ने पहले दो संदिग्धों को गिरफ्तार किया, जिन्हें यूएनएलएफ (पी) के सक्रिय कैडर बताया जा रहा है। इनके कब्जे से एक इंसास लाइट मशीन गन, तीन मैगजीन और 14 जिंदा कारतूस बरामद किए गए। अधिकारियों ने बताया कि अभियान के दौरान आरोपियों के कुछ सहयोगियों ने सुरक्षाबलों पर फायरिंग भी की, जिसके बाद जवाबी कार्रवाई की गई। स्थिति नियंत्रित होने के बाद दो अन्य संदिग्धों को भी हिरासत में लिया गया।

प्रारंभिक पूछताछ में आरोपियों ने कथित तौर पर स्वीकार किया कि वे संगठन के स्वयंभू लांस कॉर्पोरल नोरेम बिजॉय उर्फ माचा के निर्देश पर हथियार बेचने पहुंचे थे। जांच एजेंसियों के अनुसार, आरोपियों ने यह भी माना है कि वे पहले भी लूटे गए हथियारों और गोला-बारूद की अवैध बिक्री में शामिल रहे हैं।

पूछताछ से मिले इनपुट के आधार पर सुरक्षा बलों ने लामदेंग इलाके में स्थित यूएनएलएफ (पी) के एक कथित अवैध कैंप पर घेराबंदी और तलाशी अभियान चलाया। इस अभियान के दौरान पहले चरण में 29 हथियार बरामद किए गए। इनमें एके सीरीज और एम सीरीज राइफलें, पिस्तौल तथा अन्य अत्याधुनिक हथियार शामिल थे। अगले दिन सुरक्षा बलों ने तलाशी अभियान का विस्तार किया और अतिरिक्त 38 हथियारों के साथ भारी मात्रा में सैन्य उपकरण बरामद किए। अधिकारियों के मुताबिक, जब्त हथियारों में एके सीरीज राइफल, एम-सीरीज राइफल, स्नाइपर राइफल, कार्बाइन, शॉटगन, मोर्टार और आरपीजी-7 लॉन्चर जैसे हथियार शामिल हैं। इसके अलावा एंटी-ड्रोन जैमर, विस्फोटक सामग्री और अन्य सैन्य उपकरण भी बरामद किए गए हैं। सुरक्षा एजेंसियों का मानना है कि यह नेटवर्क केवल स्थानीय स्तर तक सीमित नहीं था, बल्कि हथियारों की आपूर्ति और बिक्री के लिए व्यापक तस्करी चैनल सक्रिय थे। जांच अब इस दिशा में भी की जा रही है कि बरामद हथियार कहां से लाए गए थे और इन्हें किन समूहों तक पहुंचाया जाना था।

मणिपुर पिछले कई महीनों से जातीय हिंसा और उग्रवादी गतिविधियों के कारण संवेदनशील बना हुआ है। ऐसे में बड़ी मात्रा में हथियारों की बरामदगी ने सुरक्षा एजेंसियों की चिंता और बढ़ा दी है। अधिकारियों का कहना है कि यदि यह खेप समय रहते नहीं पकड़ी जाती, तो इसका इस्तेमाल बड़े हमलों या हिंसक गतिविधियों में किया जा सकता था।

सुरक्षा बलों ने संकेत दिए हैं कि आने वाले दिनों में राज्य के संवेदनशील इलाकों में और भी व्यापक तलाशी अभियान चलाए जाएंगे। पुलिस का कहना है कि उग्रवादी संगठनों और हथियार तस्करी नेटवर्क के खिलाफ “जीरो टॉलरेंस” नीति के तहत कार्रवाई जारी रहेगी।

विशेषज्ञों का मानना है कि इस कार्रवाई ने एक बार फिर यह स्पष्ट कर दिया है कि पूर्वोत्तर में उग्रवादी नेटवर्क अभी भी सक्रिय हैं और उनके पास अत्याधुनिक हथियारों तक पहुंच बनी हुई है। हालांकि सुरक्षा बलों की ताजा कार्रवाई को एक बड़ी सफलता माना जा रहा है, जिसने संभावित खतरे को समय रहते रोकने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है।

चुनावी आचरण पर घिरे तमिलनाडु के सीएम विजय, हाईकोर्ट ने जारी किया नोटिस

चेन्नई। Madras High Court ने तमिलनाडु की राजनीति से जुड़े एक संवेदनशील मामले में सख्त रुख अपनाते हुए राज्य के नवनिर्वाचित मुख्यमंत्री C. Joseph Vijay को नोटिस जारी किया है। मामला विधानसभा चुनावों के दौरान बच्चों के कथित चुनावी इस्तेमाल और भ्रष्ट चुनावी तौर-तरीकों से जुड़ा हुआ है। अदालत ने इस मामले को गंभीर मानते हुए चुनाव आयोग से जांच करवाने की मांग वाली जनहित याचिका पर सुनवाई शुरू कर दी है।

यह मामला उस समय और अधिक चर्चा में आ गया जब अदालत ने केवल मुख्यमंत्री विजय ही नहीं, बल्कि कई अन्य प्रमुख राजनीतिक हस्तियों और संस्थाओं को भी नोटिस जारी किया। अदालत की अवकाशकालीन पीठ, जिसमें न्यायमूर्ति जी आर स्वामीनाथन और न्यायमूर्ति वी लक्ष्मण शामिल थे, ने सुनवाई के दौरान कहा कि चुनावी प्रक्रिया की शुचिता लोकतंत्र की बुनियाद है और यदि बच्चों के इस्तेमाल जैसे आरोप सामने आते हैं, तो उनकी गंभीरता से जांच होना आवश्यक है।

इस मामले में Election Commission of India, तमिलनाडु के मुख्य चुनाव अधिकारी, M. K. Stalin और Edappadi K. Palaniswami को भी नोटिस जारी किया गया है। अदालत ने सभी पक्षों से जवाब मांगा है और मामले की अगली सुनवाई 29 मई को निर्धारित की है।

याचिका कुड्डालोर जिले की अधिवक्ता एल वासुकी द्वारा दायर की गई है। याचिका में आरोप लगाया गया है कि हाल ही में संपन्न हुए तमिलनाडु विधानसभा चुनावों के दौरान लोकतांत्रिक मर्यादाओं और चुनावी नियमों का उल्लंघन हुआ। विशेष रूप से टीवीके प्रमुख और वर्तमान मुख्यमंत्री विजय पर आरोप है कि उन्होंने चुनाव प्रचार में बच्चों का इस्तेमाल कर मतदाताओं को प्रभावित करने का प्रयास किया।

याचिका में कहा गया है कि चुनाव के दौरान बच्चों को प्रचार अभियानों और राजनीतिक गतिविधियों में शामिल किया गया, जो चुनावी नैतिकता और बाल अधिकारों दोनों के लिहाज से गंभीर विषय है। इसके साथ ही याचिकाकर्ता ने अन्य कथित भ्रष्ट चुनावी गतिविधियों का भी हवाला दिया है और अदालत से पूरे मामले की निष्पक्ष जांच करवाने की मांग की है।

राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि यह मामला इसलिए भी महत्वपूर्ण हो गया है क्योंकि Tamilaga Vettri Kazhagam के संस्थापक विजय ने हाल ही में राजनीति में तेजी से उभार हासिल किया है और विधानसभा चुनावों में उनकी पार्टी की सफलता ने राज्य की पारंपरिक राजनीति को नया मोड़ दिया है। ऐसे में उनके खिलाफ लगे आरोपों और अदालत की कार्रवाई को राजनीतिक रूप से भी बेहद अहम माना जा रहा है। कानूनी विशेषज्ञों का कहना है कि चुनावों में बच्चों के इस्तेमाल को लेकर भारतीय कानून और चुनाव आयोग के दिशा-निर्देश स्पष्ट हैं। यदि किसी राजनीतिक दल या उम्मीदवार पर इस तरह के आरोप सिद्ध होते हैं, तो यह चुनावी आचार संहिता और संबंधित कानूनी प्रावधानों का उल्लंघन माना जा सकता है।

हालांकि अभी अदालत ने केवल नोटिस जारी किया है और मामले की जांच तथा जवाबों के बाद ही आगे की दिशा स्पष्ट होगी। फिलहाल मुख्यमंत्री विजय या उनकी पार्टी की ओर से इस मामले पर कोई विस्तृत सार्वजनिक प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है।

तमिलनाडु की राजनीति में यह मामला अब तेजी से चर्चा का केंद्र बनता जा रहा है। विपक्षी दल इसे चुनावी नैतिकता से जोड़कर सरकार को घेरने की कोशिश कर रहे हैं, जबकि विजय समर्थकों का कहना है कि यह राजनीतिक रूप से प्रेरित विवाद है। अब सभी की नजरें 29 मई को होने वाली अगली सुनवाई पर टिकी हैं, जहां अदालत इस मामले में आगे की प्रक्रिया और संभावित जांच को लेकर महत्वपूर्ण निर्देश दे सकती है।

बंगाल के मदरसों में अब गूंजेगा ‘वंदे मातरम’, सरकार के फैसले पर तेज हुई राजनीतिक बहस

कोलकाता। West Bengal की राजनीति और शिक्षा जगत में एक नया विवाद खड़ा हो गया है। राज्य सरकार ने प्रदेश के सभी मदरसों में सुबह की प्रार्थना सभाओं के दौरान ‘वंदे मातरम’ का गायन तत्काल प्रभाव से अनिवार्य करने का आदेश जारी किया है। यह निर्देश मदरसा शिक्षा निदेशालय की ओर से जारी किया गया है और इसे राज्य सरकार की उस हालिया नीति का विस्तार माना जा रहा है, जिसके तहत कुछ दिन पहले सभी सरकारी और सहायता प्राप्त स्कूलों में भी राष्ट्रगीत का गायन अनिवार्य किया गया था। सरकार के इस फैसले के बाद राजनीतिक हलकों, शैक्षणिक संस्थानों और सामाजिक संगठनों के बीच नई बहस शुरू हो गई है। समर्थक इसे राष्ट्रभावना को मजबूत करने वाला कदम बता रहे हैं, जबकि विपक्षी दलों और कुछ सामाजिक संगठनों ने इसे अनावश्यक और विवाद पैदा करने वाला निर्णय करार दिया है।

मदरसा शिक्षा निदेशालय के आदेश के अनुसार यह नियम राज्य के सभी मॉडल

मदरसों, सरकारी सहायता प्राप्त मदरसों, मान्यता प्राप्त मदरसों, अनुमोदित शिशु शिक्षा केंद्रों तथा माध्यमिक शिक्षा केंद्रों पर लागू होगा। इसके अलावा अल्पसंख्यक मामलों और मदरसा शिक्षा विभाग के अधीन संचालित संस्थानों को भी इस आदेश का पालन करना होगा।

सरकारी निर्देश में कहा गया है कि प्रत्येक शिक्षण संस्थान में दिन की शुरुआत राष्ट्रगीत ‘वंदे मातरम’ से की जाएगी और सभी छात्रों को इसमें भाग लेना होगा। संस्थानों के प्रधानाचार्यों और प्रशासनिक अधिकारियों को यह सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए हैं कि आदेश का सख्ती से पालन हो।

राज्य सरकार का कहना है कि इस कदम का उद्देश्य छात्रों में राष्ट्रप्रेम, अनुशासन और सांस्कृतिक चेतना को मजबूत करना है। शिक्षा विभाग के अधिकारियों के अनुसार ‘वंदे मातरम’ भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन का महत्वपूर्ण प्रतीक रहा है और इसे स्कूलों तथा मदरसों में शामिल करना राष्ट्रीय एकता को बढ़ावा देने की दिशा में उठाया गया कदम है।

हालांकि सरकार के इस फैसले के बाद विपक्षी दलों ने तीखी प्रतिक्रिया दी है। Communist Party of India (Marxist) के वरिष्ठ नेता Sujan Chakraborty ने आरोप लगाया कि राज्य सरकार शिक्षा व्यवस्था की वास्तविक समस्याओं से लोगों का ध्यान हटाने के लिए ऐसे मुद्दे उठा रही है। उन्होंने कहा कि राज्य की शिक्षा व्यवस्था पहले से ही कई चुनौतियों का सामना कर रही है और सरकार को स्कूलों और कॉलेजों की गुणवत्ता सुधारने पर ध्यान देना चाहिए।

चक्रवर्ती ने कहा कि सरकार की प्राथमिकता शिक्षा क्षेत्र को मजबूत करना होनी चाहिए, लेकिन प्रशासन इस बात में अधिक रुचि दिखा रहा है कि प्रार्थना सभा में कौन सा गीत गाया जाए। उनके अनुसार यह कदम शिक्षा से अधिक राजनीतिक संदेश देने की कोशिश प्रतीत होता है।

वहीं Indian National Congress के वरिष्ठ नेता Pradip Bhattacharya ने भी सरकार के फैसले पर सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि ‘वंदे मातरम’ ऐतिहासिक रूप से स्वतंत्रता आंदोलन और राजनीतिक आंदोलनों से जुड़ा रहा है, लेकिन इसे मदरसों में अनिवार्य बनाना संवेदनशील मुद्दा हो सकता है। उन्होंने चेतावनी दी कि इससे समाज के कुछ वर्गों में असहजता और नाराजगी पैदा हो सकती है।

राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि यह मुद्दा आने वाले समय में पश्चिम बंगाल की राजनीति में बड़ा विवाद बन सकता है। राज्य में लंबे समय से शिक्षा, पहचान और सांस्कृतिक प्रतीकों को लेकर राजनीतिक बहस होती रही है और अब मदरसों में ‘वंदे मातरम’ अनिवार्य किए जाने का फैसला उसी बहस को और तीखा कर सकता है।

दूसरी ओर कई शिक्षाविदों और राष्ट्रवादी संगठनों ने सरकार के फैसले का समर्थन किया है। उनका कहना है कि राष्ट्रगीत गाना किसी धार्मिक पहचान के खिलाफ नहीं है, बल्कि यह देश के प्रति सम्मान और एकता की भावना को मजबूत करता है। उनका तर्क है कि शैक्षणिक संस्थानों में राष्ट्रगीत और राष्ट्रीय प्रतीकों के प्रति सम्मान सिखाना लोकतांत्रिक मूल्यों का हिस्सा है।

विशेषज्ञों का यह भी कहना है कि ‘वंदे मातरम’ को लेकर देश में पहले भी कई बार बहस हो चुकी है। कुछ समूह इसे राष्ट्रीय गौरव का प्रतीक मानते हैं, जबकि कुछ वर्गों ने इसके कुछ ऐतिहासिक और धार्मिक संदर्भों को लेकर आपत्तियां जताई हैं। ऐसे में पश्चिम बंगाल सरकार का यह नया आदेश राजनीतिक और सामाजिक दृष्टि से काफी संवेदनशील माना जा रहा है।

फिलहाल राज्य सरकार अपने फैसले पर कायम दिखाई दे रही है और शिक्षा विभाग ने सभी संस्थानों को तत्काल प्रभाव से निर्देश लागू करने के आदेश दिए हैं। अब यह देखना महत्वपूर्ण होगा कि इस फैसले पर आगे कानूनी, राजनीतिक और सामाजिक स्तर पर कैसी प्रतिक्रिया सामने आती है और क्या यह मुद्दा आने वाले दिनों में और बड़ा विवाद बनता है।

नवसर्जन संस्कृति
हिन्दी

JioTV
CHENNAL NO.
2063

Jio Air Fiber
Jio Tv +
Jio Fiber
Daily Hunt
ebaba Tv
Dish Plus
DTH live OTT
Rock TV
Airtel
Amezone Fire
Rocu Tv-US.UK

देश-दुनिया के नवीनतम समाचार
प्राप्त करने के लिए आज ही
नवसर्जन संस्कृति हिंदी चेनल देखिये

संपादकीय

महंगी मशीनें विलासिता नहीं बुनियादी जरूरत

गाल बजाते राजनेता और लोक कल्याणकारी होने का दावा करती सरकारों की नाक के नीचे सरकारी अस्पतालों की कैसी बदहाली है, ये किसी से नहीं छिपा है। लोकलुभावन कार्यक्रमों पर पैसा पानी की तरह बहाने वाली सरकारों व मंत्रियों की प्राथमिकताओं में, वे सरकारी अस्पताल कभी नहीं रहे हैं, जो गरीबों व साधनविहीन लोगों का अंतिम आश्रय होते हैं। कायदे से तो सरकारों को इस मुद्दे को प्राथमिकता मानते हुए तत्काल प्रभाव से अस्पतालों की दशा सुधारनी चाहिए। लेकिन विडंबना है कि हर बार न्यायालय को ही जनहित से जुड़े मुद्दों पर सख्ती दिखाकर सरकारों को कार्रवाई करने को कहा जाता है। एक बार फिर पंजाब व हरियाणा उच्च न्यायालय के आदेश से पंजाब तथा हरियाणा सरकारों की सार्वजनिक स्वास्थ्य प्रणाली के संचालकों को एक बेहद जरूरी झटका लगा है। हाईकोर्ट ने दोनों राज्यों को निर्देश दिए हैं कि प्रत्येक जिला अस्पताल में आईसीयू सुविधाओं के साथ-साथ सीटी स्कैन और एमआरआई मशीनों की उपलब्धता सुनिश्चित की जाए। निश्चित रूप से न्यायालय के इस तरह के सकारात्मक हस्तक्षेप से स्वास्थ्य सेवाओं को लेकर सत्ताधीशों के वायदों और उनके क्रियान्वयन के बीच बढ़ती खाई ही उजागर होती है। वहीं अदालत की कार्यवाही के दौरान पंजाब सरकार की ओर से न्यायालय को सूचित किया गया कि राज्य के 23 जिलों में से केवल छह जिला अस्पतालों में ही एमआरआई की सुविधा उपलब्ध है। दूसरी ओर राज्य के अस्पतालों में दो हजार से अधिक जनरल मेडिकल ऑफिसरों के पद और अन्य सैकड़ों विशेषज्ञों के पद खाली पड़े हुए हैं। वहीं कई जिलों के सरकारी अस्पतालों में कार्यशील आईसीयू की कमी है। अदालत ने हरियाणा सरकार से भी गहन देखभाल व निदान सुविधाओं की कमियों को लेकर स्पष्टीकरण मांगा है। निस्संदेह, इन खामियों से फिर उजागर हुआ है कि अनेक सरकारी अस्पतालों में महंगे चिकित्सा उपकरण अक्सर बिना इस्तेमाल के या कम उपयोग में क्यों रहते हैं। वहीं दूसरी ओर विभाग के उच्च अधिकारियों द्वारा भी गरीब व जरूरतमंद मरीजों की तात्कालिक जरूरतों को अनदेखा ही किया जाता है।

न्यायालय की इस बात से बिल्कुल सहमत हुआ जा सकता है कि मौजूदा दौर में सीटी स्कैन,एमआरआई और आईसीयू तक मरीजों की पहुंच विलासिता नहीं, बल्कि बुनियादी स्वास्थ्य सेवा की आवश्यकता बन गई है। जो इस बात पर भी बल देता है कि सरकारें जिला स्तरीय क्रियाशील बुनियादी ढांचा बनाने के बजाय अनिश्चित काल तक आउटसोर्सिंग या रेफरल प्रणालियों पर निर्भर नहीं रह सकती हैं। वास्तव में सार्वजनिक स्वास्थ्य प्रणाली केवल खरीद की कमी से ही नहीं, बल्कि बिना योजना के भारी-भरकम खरीद की प्रवृत्ति से भी ग्रस्त है। वहीं दूसरी ओर अकसर तकनीशियनों की अनुपलब्धता से एमआरआई मशीनें स्थापित नहीं हो पाती हैं। वहीं अनुबंध समाप्त होने के कारण अक्सर वेंटिलेटर धूल खाते रहते हैं। दूसरी तरफ रेडियोलॉजिस्ट और बायोमेडिकल इंजीनियरों की अनुपस्थिति के कारण निदान सेवाओं को आउटसोर्स किया जाता है। बार-बार की गई ऑडिट रिपोर्टों से पता चलता है कि सरकारी अस्पतालों में करोड़ों रुपये के जीवन रक्षक उपकरण महीनों से लेकर वर्षों तक बेकार ही पड़े रहते हैं। जिसका खमियाजा जरूरतमंद मरीजों को उठाना पड़ता है। किसी भी अस्पताल में एक खराब सीटी स्कैनर की वजह से दुर्घटना पीड़ितों, कैंसर के मरीजों और हृदयाघात के रोगियों के उपचार में देरी होती है। दूसरी ओर सरकारी अस्पतालों में विशेषज्ञ डॉक्टरों का हर एक खाली पद कमजोर वर्ग के लोगों को महंगे निजी अस्पतालों में उपचार के लिये धकेल देता है। यह विडंबना ही है कि दूर-दराज के ग्रामीण इलाकों के मरीज अक्सर लंबी दूरी तय करके सरकारी अस्पतालों तक पहुंचते हैं। अक्सर देखा जाता है कि उन्हें या तो मशीनें काम न करने वाली मिलती हैं या चलाने वाले कर्मचारी नहीं मिलते। निर्विवाद रूप से केवल मशीनें लगाने से ही मरीजों की समस्या का समाधान नहीं हो जाता। सही मायनों में सरकारी अस्पतालों में उपकरणों की उपलब्धता के साथ ही डॉक्टरों, तकनीशियनों आदि की जवाबदेही भी सुनिश्चित होनी ही चाहिए। वास्तव में किसी भी स्वास्थ्य सेवा का मूल्यांकन खरीदी गई महंगी मशीनों से नहीं, बल्कि सही समय पर उपचार का लाभ पाने वाले मरीजों की संख्या से होता है।

हंतावायरस-इबोला से फिर स्वास्थ्य चुनौती

> “ कांगो में तेजी से फैल रहे इबोला वायरस ने चिंता बढ़ा दी है क्योंकि वहां युद्ध की वजह से संक्रमण पर काबू पाना मुश्किल है। इबोला की प्रजाति भी दुर्लभ है जिसे रोकने के लिए कम ही साधन हैं। वायरस संक्रमित लोगों में से एक-तिहाई लोगों की जान ले लेता है। वहीं हंतावायरस की नई चुनौती भी है।

कुछ दिन पहले एक क्रूज जहाज, एमवी होंडियस पर हंतावायरस के मामलों ने पूरी दुनिया का ध्यान खींचा है। अब डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कांगो में इबोला का प्रकोप स्वास्थ्य अधिकारियों के लिए नई चिंता पैदा कर रहा है। यह वायरस हफ्तों से दुनिया के एक ऐसे हिस्से में फैल रहा है, जहां गृह युद्ध की वजह से संक्रमण पर काबू पाना मुश्किल है। साथ ही, इसमें शामिल इबोला की प्रजाति भी दुर्लभ है। इसलिए इस वायरस को रोकने के लिए अधिकारियों के पास कम ही साधन उपलब्ध हैं। यह वायरस संक्रमित लोगों में से लगभग एक-तिहाई लोगों की जान ले लेता है। यह इस महामारी के फैलने का एक बहुत ही नाजुक दौर है।

विश्व स्वास्थ्य संगठन की एक प्रतिनिधि ऐन एन्सिया ने चेतावनी दी है कि डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कांगो में इबोला का प्रकोप, जिसने कम से कम 131 लोगों की जान ले ली है, शायद मूल अनुमान से कहीं ज्यादा तेजी से फैल रहा है। डॉ. एन्सिया ने बताया कि जांच से यह और भी साफ होता जा रहा है कि यह बीमारी दूसरे इलाकों में भी फैल चुकी है। अभी तक डीआर कांगो में 513 से ज्यादा मामलों का संदेह है, जबकि पड़ोसी देश युगांडा में एक व्यक्ति की मौत हो चुकी है। लंदन स्थित एमआरसी सेंटर फॉर ग्लोबल इन्फेक्शियस डिजीज एनालिसिस द्वारा जारी किए गए एक मॉडल के अनुसार, इबोला के बहुत से मामले पकड़ में नहीं आए हैं, और इस बात से भी इनकार नहीं किया जा सकता कि मामलों की संख्या 1,000 से अधिक है।

दरअसल, मौजूदा प्रकोप जितना अभी दिख रहा है, उससे कहीं ज्यादा बड़ा

है और इसका असली दायरा अभी भी अनिश्चित है। 6 अमेरिकी नागरिकों के वायरस के संपर्क में आने की सूचना मिली है। इबोला के अधिकतर मामले छोटे स्तर के ही होते हैं, लेकिन विशेषज्ञ 2014-16 में फैली महामारी को याद करके नए प्रकोप पर चिंता जाहिर कर रहे हैं। उस समय पश्चिम अफ्रीका में इबोला के सबसे बड़े प्रकोप के दौरान 28,600 लोग संक्रमित हुए थे। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने इसे ‘अंतर्राष्ट्रीय चिंता वाली सार्वजनिक स्वास्थ्य इमरजेंसी’ घोषित किया है। लेकिन इसका यह अर्थ बिल्कुल नहीं है कि हम कोविड जैसी किसी बड़ी महामारी के शुरुआती दौर में पहुंच गए हैं। पूरी दुनिया के लिए इबोला से होने वाला खतरा अब भी कम है। वर्ष 2014-16 में इबोला महामारी के दौरान भी ब्रिटेन में इबोला के केवल तीन मामले सामने आए थे, और वे सभी स्वास्थ्यकर्मी थे जो स्वेच्छा से मदद के लिए आगे आए थे। ऑक्सफर्ड यूनिवर्सिटी के पैंडेमिक साइंसेज इंस्टिट्यूट की वैज्ञानिक डॉ. अमांडा रोजेक का कहना है कि नए प्रकोप पर काबू पाने के लिए अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर आपसी तालमेल की जरूरत है। युगांडा, दक्षिण सूडान और रवांडा जैसे पड़ोसी देशों के लिए यह इबोला अब भी एक बड़ा खतरा बना हुआ है। इन देशों को व्यापार और यात्रा के घनिष्ठ संबंधों के कारण ‘उच्च जोखिम’ वाले देशों की श्रेणी में रखा गया है। इबोला एक गंभीर और जानलेवा संक्रामक बीमारी है।

दरअसल, इबोला वायरस स्वाभाविक रूप से जानवरों, मुख्य रूप से फल खाने वाले चमगादड़ों को संक्रमित करते हैं, लेकिन अगर लोग उनके सीधे संपर्क में आते हैं, तो वे भी संक्रमित हो सकते हैं। इस प्रकोप का कारण इबोला वायरस की बुंडिबुग्यो प्रजाति है। यह उन तीन प्रजातियों में से एक है, जिनके कारण संक्रमण फैलता है। बुंडिबुग्यो ने पहले केवल दो बार प्रकोप फैलाया है। वर्ष 2007 और 2012 में इसने संक्रमित लोगों में से लगभग 30 प्रतिशत की जान ले ली थी। बुंडिबुग्यो वायरस स्वास्थ्य कर्मियों के समक्ष कई तरह की चुनौतियां खड़ी करता है।

इबोला वायरस की अन्य प्रजातियों के विपरीत बुंडिबुग्यो के लिए कोई भी स्वीकृत टीका या दवा उपलब्ध नहीं है। हालांकि कुछ प्रायोगिक दवाएं अवश्य मौजूद हैं। वायरस के संक्रमण की पुष्टि करने वाले टेस्ट बहुत कारगर नहीं हैं। इस प्रकोप के शुरुआती नतीजे इबोला वायरस के लिए नेगेटिव आए थे और वायरस की पुष्टि करने के लिए अधिक उन्नत प्रयोगशाला उपकरणों की आवश्यकता पड़ी। इसमें बुंडिबुग्यो भी शामिल है। ऑक्सफर्ड विश्वविद्यालय की प्रोफेसर ट्रूडी लैंग कहती हैं कि बुंडिबुग्यो से निपटना इस प्रकोप में एक बहुत बड़ी चिंता है।

समझा जाता है कि संक्रमण होने के दो से 21 दिनों के भीतर लक्षण दिखाई देने लगते हैं। शुरुआत में ये फ्लू के लक्षणों जैसे होते हैं जिनमें बुखार, सिरदर्द और थकान शामिल हैं। लेकिन जैसे-जैसे इबोला बढ़ता है, इससे उल्टी, दस्त और शरीर के अंगों का काम करना बंद हो जाना जैसी समस्याएं होने लगती हैं। कुछ मरीजों को शरीर के अंदर और बाहर रक्तस्राव की समस्या भी हो जाती है। बुंडिबुग्यो वायरस को सीधे निशाना बनाने के लिए कोई भी स्वीकृत दवा उपलब्ध न होने के कारण इसका इलाज बेहतर सहायक देखभाल पर निर्भर करता है, जिसमें दर्द, अन्य संक्रमणों, शरीर में तरल पदार्थों और पोषण का प्रबंधन शामिल है। शुरुआती देखभाल से मरीज के बचने की संभावना बढ़ जाती है।

अफ्रीका में इबोला के मामले सामने आने से कुछ दिन पहले एक क्रूज जहाज पर कुछ यात्रियों के हंतावायरस के संक्रमित लोगों की खबर ने कोविड के दिनों की याद ताजा कर दी। छह साल पहले, मार्च 2020 में एक क्रूज जहाज रूबी प्रिंसेस के सिडनी में डॉक होने के बाद कोविड फैल गया था। जहाज से उतरे यात्रियों और चालक दल के सदस्यों में से 575 लोग कोविड से संक्रमित थे। इसके बाद यह वायरस और दूसरे लोगों में भी फैल गया। अतः अब एमवी होंडियस जहाज पर हंतावायरस की मौजूदगी पर स्वास्थ्य अधिकारियों द्वारा तत्काल सावधानी बरतना और क्वारंटीन जैसे कदम उठाना स्वाभाविक था। होंडियस के यात्री एंडीज वायरस के संपर्क में आए जो कि एक प्रकार का हंतावायरस है जो चूहों से फैलता है। एंडीज वायरस एक खतरनाक वायरस है लेकिन कोविड के साथ इसकी तुलना कुछ हद तक ही की जा सकती है। विश्व स्वास्थ्य संगठन और अनेक विशेषज्ञों का कहना है कि इस वायरस में वे विशेषताएं नहीं हैं जो इसे ‘अगला कोविड’ बना सकें। हंतावायरस एक ऐसा वायरस समूह है जो आमतौर पर चूहों, गिलहरियों और चूहों जैसी अन्य प्रजातियों (रोडेंट) द्वारा फैलाया जाता है। ज्यादातर हंतावायरस के बारे में यह नहीं मालूम है कि वे एक इंसान से दूसरे इंसान में फैलते हैं या नहीं। लेकिन एंडीज वायरस इसका अपवाद है। संक्रमित चूहों से इंसानों में फैलने के बाद यह एकमात्र ऐसा हंतावायरस है जिसके एक इंसान से दूसरे इंसान में फैलने के पुष्ट प्रमाण मौजूद हैं।

प्रेरणा

विवेक का प्रकाश

मनुष्य के जीवन में कई ऐसी शक्तियाँ होती हैं जो उसे सामान्य भीड़ से अलग बनाती हैं। धन, पद, प्रतिष्ठा और बाहरी सफलता कुछ समय के लिए आकर्षण पैदा कर सकती हैं, लेकिन जीवन को सही दिशा देने का कार्य केवल ज्ञान और विवेक ही करते हैं। ज्ञान केवल पुस्तकों में लिखे शब्दों का संग्रह नहीं होता, बल्कि वह वह प्रकाश है जो मनुष्य को अंधकार से निकालकर सत्य की ओर ले जाता है। भारत के महान दार्शनिक, शिक्षक और पूर्व राष्ट्रपति Sarvepalli Radhakrishnan का जीवन इसी सत्य का प्रतीक था। वे मानते थे कि शिक्षा का वास्तविक उद्देश्य केवल नौकरी पाना नहीं, बल्कि मनुष्य के भीतर सोचने, समझने और सही निर्णय लेने की क्षमता विकसित करना है।

एक बार विश्वविद्यालय में उनकी कक्षा चल रही थी। छात्र बड़ी गंभीरता से उनके विचार सुन रहे थे। राधाकृष्णन अपने सरल किंतु गहरे शब्दों के लिए प्रसिद्ध थे। वे कठिन से कठिन दर्शन को भी इतनी सहजता से समझाते थे कि छात्र मंत्रमुग्ध हो जाते थे। उसी दौरान एक छात्र ने अचानक खड़े होकर प्रश्न किया, “सर, दर्शन पढ़ने से जीवन में क्या बदलेगा? पेट तो इससे नहीं भरता।” यह प्रश्न सुनते ही पूरी कक्षा में सन्नाटा छा गया। कई छात्रों को लगा कि यह प्रश्न शायद गुरु का अपमान है, क्योंकि उस समय दर्शन को बहुत ऊँचा विषय माना जाता था। लेकिन राधाकृष्णन के चेहरे पर न क्रोध था और न ही असहजता। वे कुछ क्षण शांत रहे, जैसे उस प्रश्न की गहराई को महसूस कर रहे हों।

फिर उन्होंने मुस्कुराकर कहा, “तुम सही कह रहे हो—ज्ञान पेट नहीं भरता।” छात्र के चेहरे पर हल्की मुस्कान उभर आई। उसे लगा कि शायद उसका तर्क सही सिद्ध हो गया। लेकिन तभी राधाकृष्णन ने आगे कहा, “पर याद रखो, पेट भरने के लिए काम चाहिए और सही काम चुनने के लिए विवेक। दर्शन वही विवेक देता है।” पूरा वातावरण एकदम गंभीर हो गया। उनकी आवाज़ में अनुभव की शक्ति थी। वे केवल शब्द नहीं बोल रहे थे, बल्कि जीवन का सार समझा रहे थे। उन्होंने मेज़ पर रखे दीपक की ओर इशारा किया। दीपक की लौ शांत होकर जल रही थी। राधाकृष्णन बोले, “दीपक भोजन नहीं बनाता, पर बिना उसके रसोई अंधेरे में रहती है। ज्ञान भी ऐसा ही दीपक है। वह जीवन का बोझ अपने कंधों पर नहीं उठाता, लेकिन यह अवश्य बताता है कि रास्ता कौन-सा सही है।” यह सुनते ही छात्र की आँखें झुक गईं। उसे समझ में आ गया कि शिक्षा का अर्थ केवल पैसे कमाने का साधन नहीं है। शिक्षा वह शक्ति है जो मनुष्य को सही और गलत के बीच अंतर करना सिखाती है।

आज के समय में भी यह प्रसंग उतना ही प्रासंगिक है। आधुनिक समाज में शिक्षा को अधिकतर लोग केवल नौकरी और वेतन से जोड़कर देखने लगे हैं। माता-पिता बच्चों से पूछते हैं कि कौन-सा विषय अधिक पैसा देगा, कौन-सा कोर्स जल्दी नौकरी दिलाएगा। बहुत कम लोग यह सोचते हैं कि शिक्षा मनुष्य के चरित्र, दृष्टिकोण और निर्णय क्षमता को भी गढ़ती है। यदि किसी व्यक्ति के पास बहुत धन हो लेकिन विवेक न हो, तो वह अपने जीवन को गलत दिशा में ले जा सकता है। दूसरी ओर, यदि किसी के पास सीमित साधन हों लेकिन सोचने-समझने की शक्ति हो, तो वह कठिन परिस्थितियों में भी अपना मार्ग बना लेता है।

ज्ञान मनुष्य को केवल जानकारी नहीं देता, बल्कि उसके भीतर संवेदनशीलता और नैतिकता भी जगाता है। एक शिक्षित व्यक्ति केवल अपने लिए नहीं सोचता, बल्कि समाज और मानवता के हित को भी समझता है। यही कारण है कि महान शिक्षक केवल पाठ्यपुस्तकें नहीं पढ़ाते, बल्कि जीवन जीने की कला भी सिखाते हैं। राधाकृष्णन ऐसे ही गुरु थे। वे छात्रों को यह बताते थे कि मनुष्य का मूल्य उसकी कमाई से नहीं, बल्कि उसके विचारों और कर्मों से तय होता है।

जब जीवन में कठिनाइयाँ आती हैं, तब केवल डिग्रियाँ काम नहीं आतीं। उस समय मनुष्य का धैर्य, विवेक और आत्मविश्वास उसकी सबसे बड़ी शक्ति बनते हैं। कई बार व्यक्ति के सामने ऐसे अवसर आते हैं जहाँ जल्दी लाभ पाने के लिए गलत रास्ता चुनना आसान होता है। लेकिन ज्ञान का प्रकाश उसे रोकता है। वह भीतर से आवाज़ देता है कि सच्ची सफलता वही है जो ईमानदारी और सत्य के मार्ग से प्राप्त हो। यही शिक्षा का वास्तविक उद्देश्य है।

राधाकृष्णन का मानना था कि यदि शिक्षा केवल धन कमाने का साधन बन जाए, तो समाज में नैतिकता समाप्त हो जाएगी। डॉक्टर केवल पैसे के लिए इलाज करेंगे, शिक्षक केवल वेतन के लिए पढ़ाएंगे और नेता केवल सत्ता के लिए राजनीति करेंगे। लेकिन जब शिक्षा के साथ विवेक जुड़ता है, तब मनुष्य अपने कार्य को सेवा और जिम्मेदारी के रूप में देखने लगता है। यही कारण है कि भारत में गुरु को हमेशा विशेष सम्मान दिया गया। गुरु केवल ज्ञान देने वाला व्यक्ति नहीं, बल्कि अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाने वाला मार्गदर्शक माना गया।

उस छात्र ने उस दिन केवल एक उत्तर नहीं सुना था, बल्कि जीवन का गहरा सत्य समझा था। उसने जाना कि भोजन शरीर को जीवित रखता है, लेकिन ज्ञान आत्मा को दिशा देता है। बिना विवेक के मनुष्य भटक सकता है, चाहे उसके पास कितनी ही संपत्ति क्यों न हो। ज्ञान का दीपक ही वह शक्ति है जो जीवन के अंधेरे रास्तों में प्रकाश फैलाती है।

मनुष्य की सबसे बड़ी संपत्ति उसका विवेक है। धन छिन सकता है, पद समाप्त हो सकता है, लेकिन सही सोच और सही निर्णय लेने की क्षमता हमेशा उसके साथ रहती है। यही कारण है कि इतिहास में वे लोग अमर हुए जिन्होंने ज्ञान को केवल अपने लाभ के लिए नहीं, बल्कि समाज के कल्याण के लिए उपयोग किया। राधाकृष्णन का यह संदेश आज भी हर विद्यार्थी, हर शिक्षक और हर इंसान के लिए प्रेरणा है कि शिक्षा का अर्थ केवल जीविका कमाना नहीं, बल्कि जीवन को सार्थक बनाना है। जिस व्यक्ति के भीतर ज्ञान का दीपक जल उठता है, वह साधारण परिस्थितियों में भी असाधारण ऊँचाइयों तक पहुँच सकता है।

घुसपैठियों और अतिक्रमणकारियों के पास अचानक इतने पत्थर कहां से आ जाते हैं?

मुंबई के लिए मुसीबत बने बांग्लादेशी और रोहिंग्या घुसपैठियों को पुलिस और प्रशासन ने करारा सबक सिखाकर देश की आर्थिक राजधानी को बड़ी राहत दिलाई है। बांद्रा रेलवे स्टेशन के पास गरीब नगर इलाके में पश्चिम रेलवे द्वारा चलाया जा रहा अब तक का सबसे बड़ा अतिक्रमण विरोधी अभियान न केवल रेलवे भूमि को मुक्त कराने की दिशा में अहम कदम साबित हुआ, बल्कि इस कार्रवाई ने यह भी उजागर कर दिया कि किस तरह अवैध कब्जाधारी कानून व्यवस्था को चुनौती देने से भी पीछे नहीं हटते। कार्रवाई के दौरान पुलिस और रेलवे अधिकारियों पर जमकर पत्थरबाजी की गई, जिससे एक बार फिर यह सवाल खड़ा हो गया कि देश के किसी भी हिस्से में अतिक्रमण हटाने या अवैध कब्जों के खिलाफ अभियान चलते ही इन घुसपैठियों और अतिक्रमणकारियों के पास अचानक इतने पत्थर कहां से आ जाते हैं? उल्लेखनीय है कि पश्चिम रेलवे ने बांद्रा रेलवे स्टेशन के निकट गरीब नगर में फैले अवैध कब्जों को हटाने के लिए व्यापक अभियान शुरू किया है। यह मुंबई में रेलवे की अब तक की सबसे बड़ी अतिक्रमण हटाओ कार्रवाई मानी जा रही है। रेलवे के अनुसार लगभग पांच हजार दो सौ वर्ग मीटर भूमि को खाली कराया जा रहा है, जिसकी कीमत करीब छह सौ करोड़ रुपये आंकी गई है। यह इलाका हार्बर लाइन की पटरियों और बिजली व्यवस्था के बेहद करीब पहुंच चुका था, जिससे रेल संचालन और यात्रियों की सुरक्षा पर गंभीर खतरा मंडरा रहा था।

रेलवे अधिकारियों के मुताबिक यहां कई बहुमंजिला झुग्गियां फुटओवर पुलों की ऊंचाई से भी ऊपर तक बना दी गई थीं। इससे भविष्य की रेलवे परियोजनाओं और ट्रेनों की आवाजाही में बाधा उत्पन्न हो रही थी। रेलवे लंबे समय से इस भूमि को खाली कराना चाहता था, क्योंकि बांद्रा स्टेशन और बांद्रा कुर्ला परिसर के पास स्थित यह इलाका रणनीतिक दृष्टि से बेहद महत्वपूर्ण माना जाता है।

इस मामले में कानूनी प्रक्रिया वर्ष 2017 से पहले शुरू हो चुकी थी। सार्वजनिक परिसर अधिनियम के तहत कार्रवाई करते हुए 27 नवंबर 2017 को बेदखली आदेश जारी किए गए थे। इसके बाद मामला बंबई उच्च न्यायालय और फिर उच्चतम न्यायालय तक पहुंचा। इस वर्ष 29 अप्रैल को उच्च न्यायालय ने अवैध अतिक्रमण हटाने की अनुमति दी थी। बाद में उच्चतम न्यायालय ने भी इस आदेश पर रोक नहीं लगाई। इसके बाद प्रशासन ने कार्रवाई तेज कर दी।

पश्चिम रेलवे ने करीब पांच सौ झुग्गियों को हटाने के लिए चिन्हित किया, जबकि संयुक्त सर्वेक्षण में पात्र पाए गए लगभग एक सौ ढांचों को फिलहाल नहीं छुआ गया। रेलवे का कहना है कि भविष्य में इस जमीन का उपयोग उपनगरीय और लंबी दूरी की रेल सेवाओं के विस्तार के लिए किया जाएगा। कार्रवाई को सफल बनाने के लिए भारी सुरक्षा व्यवस्था की गई। करीब चार सौ पुलिसकर्मी, चार सौ रेलवे सुरक्षा बल और सरकारी रेलवे पुलिस के जवान तथा लगभग दो सौ रेलवे अधिकारी और कर्मचारी तैनात किए गए। बांद्रा स्टेशन और बांद्रा टर्मिनस के आसपास कई रास्तों को बंद कर दिया गया, जिससे भारी यातायात जाम लग गया और यात्रियों को सामान लेकर पैदल चलना पड़ा।

शुरुआत में कार्रवाई शांतिपूर्ण ढंग से चल रही थी, लेकिन दूसरे दिन दोपहर बाद माहौल अचानक तनावपूर्ण हो गया। अधिकारियों ने जब एक अवैध मस्जिद और वहां लगाए गए निजी दूरसंचार टावर को हटाने की कोशिश की तो भीड़ उग्र हो गई। प्रदर्शनकारियों ने पुलिस और प्रशासनिक टीमों पर पत्थर, बर्तन और अन्य सामान फेंकना शुरू कर दिया। इसके बाद पुलिस को हल्का बल प्रयोग करना पड़ा।

इस हिंसा में सात पुलिसकर्मी और छह प्रदर्शनकारी घायल हुए। पुलिस ने दस लोगों को हिरासत में लिया और निर्मल नगर पुलिस थाने में गैरकानूनी जमावड़ा, दंगा और सरकारी कर्मचारियों पर हमला करने के आरोप में मामला दर्ज किया गया। घायलों का उपचार भाभा अस्पताल और वीएन देसाई अस्पताल में कराया गया। एक पुलिसकर्मी और एक प्रदर्शनकारी को अस्पताल में भर्ती करना पड़ा, हालांकि दोनों की हालत स्थिर बताई गई है। अतिरिक्त पुलिस आयुक्त अभिनव देशमुख ने चेतावनी दी है कि हिंसा में शामिल लोगों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। दूसरी ओर कुछ निवासियों ने दावा किया कि वह कई दशकों से यहां रह रहे थे और उनके पास हाउस टैक्स, वाटर टैक्स तथा बिजली कनेक्शन से जुड़े दस्तावेज भी हैं। कई परिवारों ने आरोप लगाया कि उन्हें घर खाली करने के लिए पर्याप्त समय नहीं दिया गया और पुनर्वास की समुचित व्यवस्था भी नहीं की गई। कुछ लोगों ने यह भी कहा कि ईद से ठीक पहले की गई कार्रवाई ने उनकी मुश्किलें बढ़ा दी हैं।

हालांकि इन दावों और मानवीय पक्ष के बीच सबसे बड़ा सवाल यही है कि आखिर अवैध कब्जों के खिलाफ हर कार्रवाई के दौरान पत्थरबाजी की घटनाएं क्यों सामने आती हैं? चाहे देश का कोई भी राज्य हो, अतिक्रमण हटाने पहुंची पुलिस और प्रशासन पर हमला करना अब एक तयशुदा रणनीति जैसा दिखाई देता है। इससे साफ है कि कुछ तत्व कानून व्यवस्था को बिगाड़कर सरकारी कार्रवाई को रोकना चाहते हैं। मुंबई जैसे संवेदनशील और आर्थिक दृष्टि से महत्वपूर्ण शहर में इस तरह की हिंसा न केवल चिंताजनक है, बल्कि यह राष्ट्रीय सुरक्षा और शहरी व्यवस्था दोनों के लिए गंभीर चुनौती भी है।

अभियान

सूर्य कृपा से बदलती है किस्मत: आदित्य हृदय स्तोत्र का दिव्य रहस्य

सनातन धर्म में भगवान सूर्यदेव को साक्षात दिखाई देने वाला देवता माना गया है। वे केवल आकाश में चमकने वाला प्रकाश नहीं, बल्कि सम्पूर्ण सृष्टि की चेतना हैं। पृथ्वी पर जीवन की हर धड़कन सूर्य की ऊर्जा से ही चलती है। पेड़-पौधों से लेकर मनुष्य तक, हर जीव उनकी किरणों से जीवन पाता है। यही कारण है कि वेदों और पुराणों में सूर्यदेव की महिमा का विशेष वर्णन मिलता है। उन्हें तेज, तप, आत्मबल, आरोग्य, सम्मान और विजय का देवता कहा गया है। जब जीवन में निराशा घेर ले, जब बार-बार असफलता मिले, जब मनुष्य स्वयं को कमजोर और अकेला महसूस करने लगे, तब सूर्य भक्ति भीतर ऐसी ऊर्जा जगाती है जो टूटे हुए मन को फिर से खड़ा कर देती है।

हमारे शास्त्रों में वर्णित “आदित्य हृदय स्तोत्र” सूर्य उपासना का सबसे शक्तिशाली स्तोत्र माना गया है। यह केवल मंत्रों का समूह नहीं, बल्कि ऐसा दिव्य प्रकाश है जो मनुष्य के भीतर सोई हुई शक्ति को जागृत करता है। इस स्तोत्र का उल्लेख वाल्मीकि रामायण के युद्धकांड में मिलता है। जब लंका में धर्म और अधर्म का सबसे बड़ा युद्ध चल रहा था, तब एक समय ऐसा भी आया जब भगवान Rama स्वयं कुछ क्षणों के लिए चिंतित दिखाई दिए। सामने रावण जैसा महाबली योद्धा था, जिसके पास अपार शक्ति, असंख्य अस्त्र-शस्त्र और मायावी सामर्थ्य था। युद्ध लगातार चलता जा रहा था और श्रीराम की सेना भी थकने लगी थी। युद्धभूमि में भगवान राम कुछ देर मौन होकर खड़े थे। उनके मन में यह चिंता थी कि अधर्म का अंत कैसे होगा। उसी समय वहां महान तपस्वी Agastya प्रकट हुए। उन्होंने भगवान राम को गंभीर मुद्रा में देखा और समझ गए कि यह समय केवल शस्त्रों का नहीं, बल्कि आत्मबल जागृत करने का है। अगस्त्य मुनि ने श्रीराम से कहा, “हे रघुनंदन, आप सूर्यदेव की आराधना करें। आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करें। यह स्तोत्र मनुष्य के सभी भय को समाप्त करता है, शत्रुओं का नाश करता है और विजय का मार्ग खोल देता है।” इसके बाद अगस्त्य मुनि ने भगवान राम को आदित्य हृदय स्तोत्र का उपदेश दिया। श्रीराम ने पूरे श्रद्धा भाव से सूर्यदेव का ध्यान किया। जैसे-जैसे वे स्तोत्र का पाठ करते गए, वैसे-वैसे उनके भीतर नई ऊर्जा का संचार होने लगा। उनका मन शांत हो गया, भय समाप्त हो गया और चेहरे पर अद्भुत तेज लौट आया। ऐसा प्रतीत हुआ जैसे स्वयं सूर्यदेव का प्रकाश उनके भीतर उतर आया हो। इसके बाद भगवान राम ने नए आत्मविश्वास और दिव्य शक्ति के साथ युद्ध किया और अंततः रावण का वध कर धर्म की विजय स्थापित की।

यही कारण है कि आदित्य हृदय स्तोत्र को विजय का महामंत्र कहा जाता है। यह केवल बाहरी शत्रुओं को हराने का साधन नहीं, बल्कि भीतर बैठे भय, निराशा और कमजोरी को मिटाने का दिव्य उपाय है। जीवन में सबसे कठिन युद्ध बाहर नहीं, बल्कि भीतर चलता है। कई बार मनुष्य अपने डर, असफलता और नकारात्मक विचारों के कारण हार मानने लगता है। ऐसे समय में सूर्य भक्ति उसके भीतर फिर से आशा का दीप जला देती है। सूर्यदेव की सबसे बड़ी शिक्षा यही है कि कभी रुकना नहीं चाहिए। वे प्रतिदिन उदय होते हैं, चाहे मौसम कैसा भी हो। बादल उनकी रोशनी को कुछ समय के लिए ढक सकते हैं, लेकिन रोक नहीं सकते। ठीक वैसे ही जीवन में कठिनाइयां कुछ समय के लिए मनुष्य को परेशान कर सकती हैं, लेकिन यदि भीतर विश्वास और भक्ति हो, तो वह फिर से उठ खड़ा होता है। सूर्यदेव हमें कर्म, अनुशासन और निरंतरता का पाठ पढ़ाते हैं।

आज के समय में लोग बाहरी चमक-दमक के पीछे भागते-भागते भीतर से कमजोर हो गए हैं। छोटी-छोटी परेशानियां उन्हें मानसिक रूप से तोड़ देती हैं। कई लोग दिन-रात मेहनत करते हैं, लेकिन सफलता नहीं मिलने पर निराश हो जाते हैं। मन में नकारात्मकता बढ़ने लगती है। ऐसे समय में आदित्य हृदय स्तोत्र किसी आध्यात्मिक औषधि की तरह काम करता है। यह मन को स्थिर करता है और आत्मविश्वास बढ़ाता है।

ज्योतिष शास्त्र में सूर्य को आत्मा का कारक ग्रह माना गया है। सूर्य मजबूत हो तो व्यक्ति के भीतर नेतृत्व क्षमता, आत्मविश्वास और सम्मान बढ़ता है। लेकिन यदि सूर्य कमजोर हो, तो व्यक्ति को बार-बार अपमान, असफलता और मानसिक तनाव का सामना करना पड़ सकता है। ऐसे में सूर्यदेव की उपासना अत्यंत फलदायी मानी गई है। मान्यता है कि नियमित रूप से आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करने से सूर्य ग्रह मजबूत होता है और जीवन में सकारात्मक परिवर्तन आने लगते हैं। भक्ति केवल मंदिरों में दीप जलाने का नाम नहीं है। सच्ची भक्ति वह है जिसमें मन पूरी श्रद्धा के साथ ईश्वर के चरणों में समर्पित हो जाए। जब कोई व्यक्ति प्रातःकाल उगते हुए सूर्य को जल अर्पित करता है और श्रद्धा से उनका स्मरण करता है, तब उसके भीतर अद्भुत शांति का अनुभव होता है। सूर्य की सुनहरी किरणें केवल शरीर को नहीं, बल्कि आत्मा को भी प्रकाशित करती हैं। ऐसा लगता है जैसे भीतर जमा नकारात्मकता धीरे-धीरे समाप्त हो रही हो।

आदित्य हृदय स्तोत्र का नियमित पाठ करने वाले लोगों का मानना है कि इससे जीवन में नई ऊर्जा का संचार होता है। मन में सकारात्मक विचार बढ़ते हैं, निर्णय लेने की क्षमता मजबूत होती है और कठिन परिस्थितियों से लड़ने का साहस मिलता है। यह स्तोत्र व्यक्ति को यह विश्वास दिलाता है कि यदि ईश्वर की कृपा साथ हो, तो कोई भी कठिनाई स्थायी नहीं रह सकती।

रविवार का दिन सूर्यदेव को समर्पित माना गया है। इस दिन प्रातःकाल स्नान करके तांबे के पात्र से सूर्यदेव को जल अर्पित करना शुभ माना गया है। जल में लाल पुष्प, रोली और अक्षत डालकर अर्घ्य देने से सूर्यदेव प्रसन्न होते हैं। इसके बाद श्रद्धा से आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करने से विशेष फल प्राप्त होता है। कहा जाता है कि इससे करियर में सफलता, समाज में सम्मान और जीवन में स्थिरता आती है।

लेकिन सूर्य भक्ति का सबसे बड़ा चमत्कार यह नहीं कि मनुष्य को केवल धन और सफलता मिल जाए। इसका सबसे बड़ा चमत्कार यह है कि यह मनुष्य को भीतर से मजबूत बना देती है। जब मन मजबूत हो जाता है, तब जीवन की कोई भी कठिनाई बड़ी नहीं लगती। व्यक्ति असफलताओं से टूटता नहीं, बल्कि उनसे सीखकर और अधिक शक्तिशाली बन जाता है। यही सूर्यदेव की सबसे बड़ी कृपा है।

भगवान राम का जीवन भी यही सिखाता है कि भक्ति मनुष्य को कमजोर नहीं, बल्कि अजेय बनाती है। जब स्वयं मर्यादा पुरुषोत्तम राम ने युद्धभूमि में सूर्यदेव का स्मरण कर अपने भीतर नई शक्ति जगाई, तो यह स्पष्ट हो जाता है कि ईश्वर की आराधना केवल चमत्कार पाने का माध्यम नहीं, बल्कि आत्मबल जागृत करने का मार्ग है। आज की दुनिया में लोग तकनीक और भौतिक सुखों में इतने उलझ गए हैं कि भीतर की शांति खोते जा रहे हैं। बाहर से सब कुछ होने के बाद भी मन खाली महसूस करता है। ऐसे समय में सूर्य भक्ति मनुष्य को उसकी वास्तविक शक्ति का अनुभव कराती है। यह बताती है कि सच्चा प्रकाश बाहर नहीं, बल्कि भीतर है। जरूरत केवल उसे पहचानने की है। सूर्यदेव की कृपा से मनुष्य के जीवन में नया उत्साह आता है। उसका आत्मविश्वास बढ़ता है और वह हर परिस्थिति का सामना करने के लिए तैयार हो जाता है। धीरे-धीरे उसका भय समाप्त होने लगता है और मन में सकारात्मकता का प्रकाश फैलने लगता है। यही कारण है कि सनातन धर्म में सूर्य उपासना को अत्यंत चमत्कारी और कल्याणकारी माना गया है। आदित्य हृदय स्तोत्र केवल श्लोकों का पाठ नहीं, बल्कि आत्मा को जागृत करने वाला दिव्य मंत्र है। यह मनुष्य को यह विश्वास दिलाता है कि चाहे अंधेरा कितना भी गहरा क्यों न हो, सूर्य का प्रकाश उसे मिटा सकता है। जो व्यक्ति श्रद्धा और विश्वास के साथ सूर्यदेव की आराधना करता है, उसके जीवन में धीरे-धीरे परिवर्तन आने लगता है। उसका मन शांत होता है, आत्मबल मजबूत होता है और वह हर मुश्किल से लड़ने की शक्ति प्राप्त कर लेता है। सूर्यदेव केवल संसार को प्रकाश नहीं देते, वे श्रद्धालुओं के जीवन को भी रोशन कर देते हैं। उनकी भक्ति मनुष्य को निराशा से निकालकर आशा की ओर ले जाती है। जब मनुष्य पूरी श्रद्धा के साथ सूर्यदेव का स्मरण करता है, तब उसके भीतर ऐसी दिव्य शक्ति जागृत होती है जो उसे हर परिस्थिति में विजय दिलाने का सामर्थ्य देती है। यही आदित्य हृदय स्तोत्र का सबसे बड़ा रहस्य है—यह केवल शब्द नहीं, बल्कि वह दिव्य प्रकाश है जो टूटे हुए मनुष्य को फिर से खड़ा कर देता है और उसके जीवन को नई दिशा दे देता है।

PRGI NO. GJHIN/25/A2786 Printed, Published & Owned by RAGINI JIGNESHKUMAR VAGHELA and Printed By (1) JIGNESH RASHIKBHAI GAJJAR at Vansh Corporation, A/8, Shayona Golden Estate, Shahibag, Ahmedabad - 380 004
(2) DESAI RAHUL MAHESHBHAI at Bhavani Offset, “Bhatiya Ni Wadi, Opp Kalupur Railway Station, Kalupur, Ahmedabad-380 002. (3) HADIK MAHESHBHAI DESAI at Bhoomi Offset, “Bhatiya Ni Wadi, Opp Kalupur Railway Station, Kalupur, Ahmedabad-380 002
and Published from B/13, Sneh Plaza Shopping Center, I.O.C. Road, Chandkheda, Ahmedabad - 382 424. Editor : JIGNESHKUMAR PATHABHAI VAGHELA
Regd.Office : B/13, Sneh Plaza Shopping Center, I.O.C. Road, Chandkheda, Ahmedabad - 382 424 Gujarat,India. Phone : (o) 7698333307 (M) 8485951747,7096333307
Email:navsarjansanskruti2016@gmail.com*navsarjansanskruti2016@yahoo.com*Website : www.navsarjansanskruti.com

प्रदेश की अर्थव्यवस्था को नई उड़ान देने की तैयारी, प्रति व्यक्ति आय बढ़ाने पर योगी सरकार का जोर

लखनऊ। उत्तर प्रदेश को देश की सबसे तेज़ी से विकसित होती अर्थव्यवस्थाओं में शामिल करने की दिशा में राज्य सरकार ने एक बार फिर बड़ा रोडमैप सामने रखा है। मुख्यमंत्री Yogi Adityanath ने गुरुवार को इन्वेस्ट यूपी और जीबीसी 5.0 की समीक्षा बैठक में अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिए कि प्रदेश के हर जनपद तक निवेश का लाभ पहुंचना चाहिए और विकास केवल बड़े शहरों तक सीमित नहीं रहना चाहिए। उन्होंने कहा कि राज्य की प्रति व्यक्ति आय बढ़ाने के लिए मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर का तेज़ी से विस्तार आवश्यक है, क्योंकि रोजगार और आर्थिक विकास का सबसे बड़ा आधार यही क्षेत्र बन सकता है।

बैठक में अधिकारियों ने जानकारी दी कि प्रदेश में अब तक सात लाख करोड़ रुपये से अधिक के निवेश प्रस्ताव धरातल पर उतरने की प्रक्रिया में हैं। यह निवेश प्रस्ताव अलग-अलग सेक्टरों से जुड़े हुए हैं और इनके लागू होने पर राज्य में रोजगार के नए अवसर पैदा होने की संभावना है। बैठक के दौरान लीड्स 2025 रैंकिंग में उत्तर प्रदेश को मिले 'एग्जेम्प्लर अवार्ड' को भी मुख्यमंत्री को समर्पित किया गया। अधिकारियों ने दावा किया कि लॉजिस्टिक्स, इंफ्रास्ट्रक्चर और औद्योगिक विकास के क्षेत्र में उत्तर प्रदेश अब देश के अग्रणी राज्यों में शामिल हो चुका है।

मुख्यमंत्री के समक्ष जीबीसी 5.0 के आयोजन का विस्तृत खाका भी प्रस्तुत किया गया। इस आयोजन और प्रदर्शनी को आठ प्रमुख जोनों में विभाजित किया गया है, जिनमें 'व्हाई यूपी', इंफ्रास्ट्रक्चर ट्रांसफॉर्मेशन, डिफेंस एवं एयरोस्पेस, ईवी और ग्रीन एनर्जी, इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग, टेक्सटाइल्स, टूरिज्म और फूड प्रोसेसिंग जैसे महत्वपूर्ण क्षेत्र शामिल हैं। सरकार का उद्देश्य इन क्षेत्रों के माध्यम से राज्य को निवेशकों के लिए और अधिक आकर्षक बनाना है।

बैठक में विशेष रूप से डिफेंस कॉरिडोर परियोजना पर भी चर्चा हुई। अधिकारियों ने बताया कि इस कॉरिडोर में तेजी से भूमि की मांग बढ़ रही है, जिसके लिए पर्याप्त जमीन उपलब्ध कराना सरकार के लिए प्राथमिकता बन गया है। मुख्यमंत्री ने निर्देश दिया कि पुराने आवंटित प्रोजेक्ट्स की भी समीक्षा की जाए, खासकर उन परियोजनाओं की जिनमें अब तक निवेश शुरू नहीं हो पाया है। उन्होंने यह भी कहा कि निवेशकों की समस्याओं का समाधान समयबद्ध और पारदर्शी तरीके से किया जाए ताकि किसी भी प्रकार की देरी न हो।

इलेक्ट्रॉनिक्स सेक्टर को लेकर बैठक में बताया गया कि अब तक 8,050 करोड़ रुपये से अधिक के निवेश प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं। इसके अलावा स्टील एवं सीमेंट सेक्टर में 12,232 करोड़ रुपये, जीसीसी (ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर) में 2,487 करोड़ रुपये, टेक्सटाइल्स में 1,321 करोड़ रुपये और ऑटोमोबाइल सेक्टर में 722 करोड़ रुपये के निवेश प्रस्ताव सामने आए हैं। यह आंकड़े इस बात की ओर संकेत करते हैं कि प्रदेश में औद्योगिक निवेश का दायरा लगातार बढ़ रहा है और अलग-अलग सेक्टरों में कंपनियों की रुचि भी तेज हो रही है।

अंतरराष्ट्रीय स्तर पर निवेश आकर्षित करने के लिए सरकार की रणनीति भी तेज हो गई है। समीक्षा बैठक में कंट्री डेस्क की रिपोर्ट पेश की गई, जिसमें बताया गया कि जापान से लगभग 50 हजार करोड़ रुपये, सिंगापुर से 40 हजार करोड़ रुपये, जर्मनी और यूनाइटेड किंगडम से पांच-पांच हजार करोड़ रुपये, ताइवान से तीन हजार करोड़ रुपये, संयुक्त अरब अमीरात से 2,074 करोड़ रुपये और दक्षिण कोरिया से 1,600 करोड़ रुपये तक के संभावित निवेश प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं। इसके साथ ही अगस्त में जापान और सिंगापुर के लिए बिजनेस मिशन यात्रा भी प्रस्तावित की गई है, जिसका उद्देश्य विदेशी निवेश को और अधिक मजबूती देना है।

सरकार का फोकस केवल निवेश आकर्षित करने तक सीमित नहीं है, बल्कि उसे धरातल पर लागू कराने पर भी है। मुख्यमंत्री ने स्पष्ट कहा कि केवल प्रस्तावों की घोषणा पर्याप्त नहीं है, बल्कि उन्हें वास्तविक परियोजनाओं में बदलना जरूरी है। इसी दिशा में निवेशकों के साथ निरंतर संवाद और उनकी समस्याओं के त्वरित समाधान पर जोर दिया गया है।

बैठक में 'उत्तर प्रदेश रक्षा एवं एफडीआई कॉन्क्लेव 2026' का प्रस्तुतीकरण भी किया गया, जिसे लखनऊ में आयोजित करने की योजना है। इस कॉन्क्लेव में रक्षा मंत्रालय, सार्वजनिक क्षेत्र की रक्षा इकाइयों, वैश्विक एयरोस्पेस कंपनियों, एमएसएमई और स्टार्टअप्स की भागीदारी सुनिश्चित की जाएगी। इसका उद्देश्य उत्तर प्रदेश को डिफेंस और हाई-टेक मैन्युफैक्चरिंग का राष्ट्रीय केंद्र बनाना है।

सरकार की रणनीति स्पष्ट है कि आने वाले वर्षों में उत्तर प्रदेश को एक औद्योगिक शक्ति के रूप में स्थापित किया जाए, जहां केवल बड़े शहर ही नहीं बल्कि छोटे जिलों तक भी निवेश और रोजगार का लाभ पहुंचे। यह मॉडल राज्य की आर्थिक संरचना को मजबूत करने के साथ-साथ युवाओं के लिए बड़े पैमाने पर रोजगार के अवसर भी पैदा कर सकता है।

इस पूरी समीक्षा बैठक से यह संकेत मिला है कि प्रदेश सरकार अब विकास के अगले चरण में प्रवेश कर रही है, जहां लक्ष्य केवल योजनाएं बनाना नहीं, बल्कि उन्हें जमीन पर सफलतापूर्वक लागू करना है। यदि निवेश प्रस्तावों का बड़ा हिस्सा वास्तविक परियोजनाओं में बदलता है, तो आने वाले वर्षों में उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था में उल्लेखनीय बदलाव देखने को मिल सकता है।

सोना वायदा 703 रुपये और चांदी वायदा 3700 रुपये लुढ़काः क्रूड ऑयल वायदा 250 रुपये तेज

मुंबईः देश के अग्रणी कमोडिटी डेरिवेटिव्स एक्सचेंज एमसीएक्स पर कमोडिटी वायदा, ऑप्शंस और इंडेक्स फ्यूचर्स में 175068.52 करोड़ रुपये का टर्नओवर दर्ज हुआ। कमोडिटी वायदाओं में 26216.95 करोड़ रुपये का कारोबार हुआ, जबकि कमोडिटी ऑप्शंस में 148851.57 करोड़ रुपये का नॉशनल टर्नओवर हुआ। कमोडिटी ऑप्शंस में कुल प्रीमियम टर्नओवर 2282.45 करोड़ रुपये का हुआ।

कीमती धातुओं में सोना-चांदी के वायदाओं में 16208.80 करोड़ रुपये की खरीद बेच की गई। एमसीएक्स सोना जून वायदा सत्र के आरंभ में 159900 रुपये के भाव पर खुलकर, 159992 रुपये के दिन के उच्च और 159105 रुपये के नीचले स्तर को छूकर, 160006 रुपये के पिछले बंद के सामने 703 रुपये या 0.44 फीसदी लुढ़ककर 159303 रुपये प्रति 10 ग्राम बोला गया। गोल्ड-गिनी मई वायदा 211 रुपये या 0.17 फीसदी घटकर 127599 रुपये प्रति 8 ग्राम के भाव पर ट्रेड हो रहा था। गोल्ड-पेटल मई वायदा 41 रुपये या 0.26 फीसदी घटकर 15966 रुपये प्रति 1 ग्राम के भाव पर ट्रेड हो रहा था। सोना-मिनी जून वायदा 158886 रुपये पर खुलकर, ऊपर में 159550 रुपये और नीचे में 158521 रुपये पर पहुंचकर, 634 रुपये या 0.4 फीसदी घटकर 158714 रुपये प्रति 10 ग्राम के भाव पर ट्रेड हो रहा था। गोल्ड-टेन मई वायदा प्रति 10 ग्राम 159160 रुपये पर खुलकर, ऊपर में 159510 रुपये और नीचे में 158664 रुपये पर पहुंचकर, 159395 रुपये के पिछले बंद के सामने 495 रुपये या 0.31 फीसदी घटकर 158900 रुपये प्रति 10 ग्राम के भाव पर ट्रेड हो रहा था।

चांदी के वायदाओं में चांदी जुलाई वायदा 272275 रुपये पर खुलकर, ऊपर में 273196 रुपये और नीचे में 269601 रुपये पर पहुंचकर, 274265 रुपये के पिछले बंद के सामने 3700 रुपये या 1.35 फीसदी घटकर 270565 रुपये प्रति किलो के भाव पर ट्रेड हो रहा था। इनके अलावा चांदी-मिनी जून वायदा 3138 रुपये या 1.13 फीसदी लुढ़ककर 274469 रुपये प्रति किलो बोला गया। जबकि चांदी-माइक्रो जून वायदा 3072 रुपये या 1.11 फीसदी गिरकर

274569 रुपये प्रति किलो हुआ।

मेटल वर्ग में 3768.40 करोड़ रुपये के ट्रेड दर्ज हुए। तांबा मई वायदा 10.5 रुपये या 0.78 फीसदी घटकर 1341.55 रुपये प्रति किलो के भाव पर ट्रेड हो रहा था। जबकि जस्ता मई वायदा 80 पैसे या 0.22 फीसदी टूटकर 369.6 रुपये प्रति किलो के भाव पर पहुंचा। इसके सामने एल्यूमीनियम मई वायदा 3.5 रुपये या 0.91 फीसदी तेज होकर यह कॉन्ट्रैक्ट 389.55 रुपये प्रति किलो पर आ गया। जबकि सीसा मई वायदा 20 पैसे या 0.1 फीसदी बढ़कर 202.4 रुपये प्रति किलो के भाव पर ट्रेड हो रहा था।

इन जिंसों के अलावा कारोबारियों ने एनर्जी सेगमेंट में 6165.37 करोड़ रुपये के सौदे किए। एमसीएक्स क्रूड ऑयल जून वायदा सत्र के आरंभ में 9599 रुपये के भाव पर खुलकर, 9787 रुपये के दिन के उच्च और 9384 रुपये के नीचले स्तर को छूकर, 250 रुपये या 2.64 फीसदी की बढ़त के साथ 9713 रुपये प्रति बैरल के भाव पर कारोबार कर रहा था। जबकि क्रूड ऑयल-मिनी जून वायदा 256 रुपये या 2.71 फीसदी तेज होकर यह कॉन्ट्रैक्ट 9713 रुपये प्रति बैरल पर आ गया। इनके अलावा नैचुरल गैस मई वायदा सत्र के आरंभ में 292.2 रुपये के भाव पर खुलकर, 293.3 रुपये के दिन के उच्च और 289.2 रुपये के नीचले स्तर को छूकर, 291.4 रुपये के पिछले बंद के सामने 40 पैसे या 0.14 फीसदी के सुधार के साथ 291.8 रुपये प्रति एमएमबीटीयू के भाव पर कारोबार कर रहा था। जबकि नैचुरल गैस-मिनी मई वायदा 40 पैसे या 0.14 फीसदी बढ़कर 291.8 रुपये प्रति एमएमबीटीयू के भाव पर ट्रेड हो रहा था।

▸▸ कमोडिटी वायदाओं में 26216.95 करोड़ रुपये और कमोडिटी ऑप्शंस में 148851.57 करोड़ रुपये का दर्ज हुआ टर्नओवर : सोना-चांदी के वायदाओं में 16208.80 करोड़ रुपये का हुआ कारोबार

कृषि जिंसों में मेंथा ऑयल मई वायदा 991 रुपये पर खुलकर, 7.3 रुपये या 0.74 फीसदी गिरकर 985 रुपये प्रति किलो के भाव पर पहुंचा।

कारोबार की दृष्टि से एमसीएक्स पर सोना के विभिन्न अनुबंधों में 8458.73 करोड़ रुपये और चांदी के विभिन्न अनुबंधों में 7750.08 करोड़ रुपये की खरीद बेच की गई। इसके अलावा तांबा के वायदाओं में 2238.92 करोड़ रुपये, एल्यूमीनियम और एल्यूमीनियम-मिनी के वायदाओं में 824.74 करोड़ रुपये, सीसा और सीसा-मिनी के वायदाओं में 20.02 करोड़ रुपये, जस्ता और जस्ता-मिनी के वायदाओं में 677.40 करोड़ रुपये का कारोबार हुआ।

इन जिंसों के अलावा क्रूड ऑयल और क्रूड ऑयल-मिनी के वायदाओं में 4788.56 करोड़ रुपये के ट्रेड दर्ज हुए। जबकि नैचुरल गैस और नैचुरल गैस-मिनी के वायदाओं में 1358.63 करोड़ रुपये का कारोबार हुआ। मेंथा ऑयल के वायदा में 2.89 करोड़ रुपये की खरीद बेच की गई।

ओपन इंटरेस्ट सोना के वायदाओं में 9910 लोट, सोना-मिनी के वायदाओं में 61851 लोट, गोल्ड-गिनी के वायदाओं में 20358 लोट, गोल्ड-पेटल के वायदाओं में 312616 लोट और गोल्ड-टेन के वायदाओं में 45625 लोट के स्तर पर था। जबकि चांदी के वायदाओं में 10197 लोट, चांदी-मिनी के वायदाओं में 24867 लोट और चांदी-माइक्रो वायदाओं में 79037 लोट के स्तर पर था। क्रूड ऑयल के वायदाओं में 16436 लोट और नैचुरल गैस के वायदाओं में 25336 लोट के स्तर पर था।

कमोडिटी ऑप्शंस ऑन फ्यूचर्स में क्रूड ऑयल जून 12000 रुपये की स्ट्राइक प्राइस का कॉल ऑप्शन प्रति बैरल 54.6 रुपये की बढ़त के साथ 213.5 रुपये हुआ। जबकि नैचुरल गैस मई 300 रुपये की स्ट्राइक प्राइस का कॉल ऑप्शन प्रति एमएमबीटीयू 95 पैसे की नरमी के साथ 1.4 रुपये हुआ।

सोना मई 165000 रुपये की स्ट्राइक प्राइस का कॉल ऑप्शन प्रति 10 ग्राम 81.5 रुपये की गिरावट के साथ 282.5 रुपये हुआ। इसके सामने चांदी मई 300000 रुपये की स्ट्राइक प्राइस का कॉल ऑप्शन प्रति किलो 188 रुपये की गिरावट के साथ 470 रुपये हुआ। तांबा मई 1350 रुपये की स्ट्राइक प्राइस का कॉल ऑप्शन प्रति किलो 5.64 रुपये की गिरावट के साथ 5 रुपये हुआ। जस्ता मई 410 रुपये की स्ट्राइक प्राइस का कॉल ऑप्शन प्रति किलो 7 पैसे की नरमी के साथ 0.1 रुपये हुआ।

पुट ऑप्शंस में क्रूड ऑयल जून 8000 रुपये की स्ट्राइक प्राइस का पुट ऑप्शन प्रति बैरल 27.8 रुपये की गिरावट के साथ 181.5 रुपये हुआ। जबकि नैचुरल गैस मई 290 रुपये की स्ट्राइक प्राइस का पुट ऑप्शन प्रति एमएमबीटीयू 75 पैसे की नरमी के साथ 3.8 रुपये हुआ। सोना मई 155000 रुपये की स्ट्राइक प्राइस का पुट ऑप्शन प्रति 10 ग्राम 23.5 रुपये की बढ़त के साथ 435.5 रुपये हुआ। इसके सामने चांदी मई 250000 रुपये की स्ट्राइक प्राइस का पुट ऑप्शन प्रति किलो 10.5 रुपये की गिरावट के साथ 770 रुपये हुआ। तांबा मई 1340 रुपये की स्ट्राइक प्राइस का पुट ऑप्शन प्रति किलो 1.86 रुपये की बढ़त के साथ 7.1 रुपये हुआ। जस्ता मई 370 रुपये की स्ट्राइक प्राइस का पुट ऑप्शन प्रति किलो 91 पैसे के सुधार के साथ 2.5 रुपये हुआ।

गांव की चौपाल में मुख्यमंत्री की सख्ती और संवेदनशीलता दोनों दिखी, शिकायत मिलते ही अफसर पर गिरी गाज

बांसवाड़ा। राजस्थान के मुख्यमंत्री Bhajan Lal Sharma का गुरुवार सुबह एक अनोखा और जनसंपर्क से भरा हुआ अंदाज देखने को मिला, जब उन्होंने आदिवासी बहुल क्षेत्र के सुदूर गांव चुड़ादा में ग्रामीणों के बीच समय बिताया। "ग्राम विकास चौपाल" कार्यक्रम के तहत रात्रि विश्राम के बाद मुख्यमंत्री सुबह-सुबह खुद गांव की गलियों में टहलने निकले और आम लोगों से सीधे संवाद किया। पीपल के पेड़ के नीचे लगी चौपाल में उन्होंने ग्रामीणों के साथ चाय पर चर्चा की और सरकार की योजनाओं के बारे में फीडबैक लिया।

मुख्यमंत्री ने इस दौरान कहा कि राज्य सरकार पंडित दीनदयाल उपाध्याय के 'अंत्योदय' विचार को जमीन पर उतारने के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने स्पष्ट किया कि सरकार की प्राथमिकता गांव, गरीब, किसान और समाज के अंतिम व्यक्ति तक योजनाओं का लाभ पहुंचाना है। उनके इस संवाद में कई ग्रामीणों ने अपनी समस्याएं खुलकर सामने रखीं और प्रशासनिक व्यवस्था को लेकर शिकायतें भी साझा कीं।

इसी दौरान एक गंभीर मामला सामने आया जब ग्रामीणों और विभागीय कर्मचारियों ने कुशलगढ़ के खंड मुख्य चिकित्सा अधिकारी (CMHO) के खिलाफ वित्तीय अनियमितताओं की शिकायत मुख्यमंत्री के सामने रखी। शिकायत को मुख्यमंत्री ने बेहद गंभीरता से लिया और मौके पर ही अधिकारियों को कार्रवाई के निर्देश दिए। इसके बाद संबंधित चिकित्सा अधिकारी को तत्काल APO (Awaiting Posting Order) कर दिया गया। इस कार्रवाई ने मौके पर मौजूद ग्रामीणों के बीच प्रशासनिक सख्ती का संदेश दिया।

मुख्यमंत्री ने साफ कहा कि सरकारी योजनाओं और जनता के हितों से जुड़े मामलों में किसी भी तरह की लापरवाही या भ्रष्टाचार को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। उन्होंने अधिकारियों को चेतावनी देते हुए कहा कि जनता के विश्वास के साथ खिलवाड़ करने वालों पर तुरंत और सख्त कार्रवाई की जाएगी।

इसी चौपाल के दौरान एक भावुक पल तब आया जब रोशनी कलाल नाम की एक महिला मुख्यमंत्री से मिली। महिला ने बताया कि उसका बेटा गंभीर बीमारी 'सेरेब्रल पाल्सी' से पीड़ित है और इलाज में परिवार को काफी कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। उसने मुख्यमंत्री से अनुरोध किया कि उसके पति हेमंत कुमार कलाल, जो PHED विभाग में सहायक अभियंता हैं, का सागवाड़ा से बांसवाड़ा तबादला किया जाए ताकि वे अपने बच्चे की बेहतर देखभाल कर सकें। मुख्यमंत्री ने महिला की बात को गंभीरता और संवेदनशीलता से सुना और तुरंत अधिकारियों को आवश्यक कार्रवाई के निर्देश दिए। कुछ ही समय में संबंधित पदस्थापन आदेश जारी कर दिए गए, जिससे मौके पर मौजूद लोगों ने सरकार की त्वरित कार्यशैली की सराहना की।

इसके अलावा मुख्यमंत्री ने क्षेत्र के विकास से जुड़ी कई स्थानीय मांगों को भी मौके पर ही मंजूरी दी। ठुम्मठ गांव में मां बाड़ी केंद्र के निर्माण के लिए 16.20 लाख रुपये की स्वीकृति दी गई। वहीं ठुम्मठ चौराहा पर सिंगल फेज ट्यूबवेल निर्माण के लिए 20 लाख रुपये मंजूर किए गए। चुड़ादा गांव में स्थित मामा बालेश्वर दयाल मंदिर परिसर के सौंदर्यीकरण और इंटरलॉकिंग कार्यों के लिए 7 लाख रुपये की स्वीकृति दी गई।

इसके साथ ही राजकीय विद्यालय में दो नए कक्षा-कक्षों के निर्माण और दूध संकलन केंद्र स्थापित करने के निर्देश भी दिए गए। इन घोषणाओं से ग्रामीणों में उत्साह देखा गया और लोगों ने इसे क्षेत्र के विकास की दिशा में महत्वपूर्ण कदम बताया। मुख्यमंत्री का यह दौरा न केवल प्रशासनिक सक्रियता का उदाहरण बना, बल्कि इसमें जनसंवाद और जमीनी समस्याओं के समाधान की स्पष्ट झलक भी दिखाई दी। गांव में रुककर लोगों से सीधे बातचीत करना, उनकी समस्याएं सुनना और तुरंत निर्णय लेना इस बात का संकेत माना जा रहा है कि सरकार जमीनी स्तर पर प्रशासन को और अधिक जवाबदेह बनाने की कोशिश कर रही है।

चौपाल के दौरान मुख्यमंत्री का यह अंदाज जहां एक ओर सख्त कार्रवाई के लिए चर्चा में रहा, वहीं दूसरी ओर उनकी संवेदनशीलता ने भी लोगों का ध्यान खींचा। ग्रामीणों से सीधे संवाद और मौके पर फैसलों ने पूरे कार्यक्रम को विशेष बना दिया।

रील लाइफ में एक्टर, रियल लाइफ में फरार हत्यारा–12 साल बाद पैरोल जंपर की फिल्मी अंदाज में गिरफ्तारी

अहमदाबाद। गुजरात में अपराध और सिनेमा की दुनिया को जोड़ देने वाला एक चौंकाने वाला मामला सामने आया है, जिसमें Gujarat Police की क्राइम ब्रांच ने 12 साल से फरार चल रहे एक शातिर अपराधी को गिरफ्तार किया है। यह मामला किसी थ्रिलर फिल्म की कहानी से कम नहीं है, जहां उम्रकैद की सजा काट रहा एक कैदी पैरोल पर बाहर आने के बाद पहचान बदलकर न केवल फरार हो गया, बल्कि मायानगरी मुंबई में जाकर फिल्म और थिएटर की दुनिया का हिस्सा भी बन गया।

आरोपी हेमंत मोदी वर्ष 2005 के एक हत्या मामले में दोषी ठहराया गया था और उसे उम्रकैद की सजा सुनाई गई थी। वह मेहसाणा जिला जेल में सजा काट रहा था, लेकिन वर्ष 2014 में गुजरात हाईकोर्ट द्वारा 30 दिनों की पैरोल मिलने के बाद वह जेल वापस नहीं लौटा और फरार हो गया। इसके बाद उसे आधिकारिक रूप से 'पैरोल जंपर' घोषित कर दिया गया।

पैरोल के बाद फरार हुए हेमंत मोदी ने अपनी पहचान पूरी तरह बदल ली और मुंबई में जाकर छिप गया। जांच एजेंसियों के अनुसार, उसने नए नाम और पहचान के साथ मनोरंजन जगत में कदम रखा और धीरे-धीरे फिल्मों, वेब सीरीज और नाटकों में सहायक कलाकार के रूप में काम करना शुरू कर दिया। वह बड़े प्रोडक्शन हाउस से जुड़ा और कई प्रोजेक्ट्स में बैकग्राउंड और सपोर्टिंग रोल निभाता रहा।

चौंकाने वाली बात यह है कि आरोपी ने खुद को इतने लंबे समय तक छिपाए रखा कि वह बड़े-बड़े कलाकारों और सुपरस्टार्स के साथ स्क्रीन पर नजर आने लगा। पुलिस की जानकारी के मुताबिक, उसने Amitabh Bachchan और Aamir Khan जैसे सितारों के साथ जुड़ी फिल्मों में भी काम किया, जिनमें Thugs of Hindostan और Jayeshbhai Jordaar जैसी चर्चित फिल्मों का नाम सामने आया है। इसके अलावा उसने थिएटर और स्टेज शोज में भी सक्रिय रूप से भाग लिया।

हेमंत मोदी केवल फिल्मों तक सीमित नहीं रहा, बल्कि उसने रंगमंच की दुनिया में भी अपनी पहचान बनाने की कोशिश की। बताया जा रहा है कि वह कई नाटकों में अभिनय कर रहा था और नियमित रूप से मंच पर प्रस्तुति देता था। इसी बीच उसने अपनी असली पहचान पूरी तरह छिपाए रखी, जिससे पुलिस लंबे समय तक उसे ट्रेस नहीं कर सकी।

यह पूरा मामला उस समय उजागर हुआ जब गुजरात क्राइम ब्रांच को सूचना मिली कि संदिग्ध व्यक्ति अहमदाबाद के घीकांटा मेट्रो स्टेशन के पास देखा गया है। इसके बाद पुलिस ने तुरंत जाल बिछाया और बुधवार दोपहर करीब एक बजे उसे गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तारी के समय वह सामान्य जीवन जीता हुआ दिखाई दे रहा था और किसी को उस पर शक नहीं था कि वह इतने गंभीर आपराधिक मामले में वांछित है।

इस मामले की पृष्ठभूमि भी बेहद गंभीर रही है। वर्ष 2005 में अहमदाबाद में हेमंत मोदी के खिलाफ हत्या, दंगा भड़काने और आपराधिक साजिश जैसे गंभीर आरोपों में मामला दर्ज किया गया था। बाद में उसे दोषी ठहराकर उम्रकैद की सजा सुनाई गई थी। उस पर भारतीय दंड संहिता की कई गंभीर धाराएं लगी थीं, जिनमें 302 (हत्या), 147, 148 (दंगा), 149 (गैरकानूनी जमावड़ा) और 120B (आपराधिक साजिश) शामिल थीं।

2014 में पैरोल पर बाहर आने के बाद उसने न्याय व्यवस्था को चकमा देते हुए फरार होने का रास्ता चुना। जुलाई 2014 में अदालत ने उसे आधिकारिक रूप से फरार घोषित कर दिया था। इसके बाद वह लगातार 12 वर्षों तक कानून से बचता रहा और अपनी पहचान छुपाकर सामान्य जीवन जीता रहा।

पुलिस अधिकारियों के अनुसार, आरोपी का जीवन पूरी तरह फिल्मी स्क्रिप्ट जैसा था। दिन में वह सामान्य कलाकार की तरह शूटिंग और रिहर्सल करता था, जबकि रात में वह एक ऐसे व्यक्ति के रूप में जी रहा था जो कानून से भाग रहा था। यह दोहरी जिंदगी उसने इतने लंबे समय तक कैसे छुपाई, यह अब जांच का विषय बना हुआ है।

गिरफ्तारी के बाद उसे फिर से मेहसाणा जेल भेजा जा रहा है, जहां उसे अपनी बाकी की उम्रकैद की सजा पूरी करनी होगी। पुलिस अब यह भी जांच कर रही है कि फरार रहने के दौरान उसे किन-किन लोगों ने मदद की और क्या उसने किसी अन्य जगह पर भी अपनी पहचान बदलकर अवैध रूप से दस्तावेज बनाए थे।

यह मामला केवल एक अपराधी की गिरफ्तारी नहीं है, बल्कि यह भी दर्शाता है कि कैसे तकनीक, पहचान और नेटवर्क का इस्तेमाल कर अपराधी लंबे समय तक कानून से बच सकते हैं। हालांकि अंततः कानून के हाथ लंबे साबित हुए और 12 साल बाद इस फिल्मी अंदाज में उसकी कहानी का एक अध्याय समाप्त हो गया।

5 जून की पोरबंदर-मुजफ्फरपुर एक्सप्रेस परिवर्तित मार्ग से चलेगी

यात्रियों की सुविधा एवं सुरक्षित रेल संचालन सुनिश्चित करने के उद्देश्य से पूर्वोत्तर रेलवे के वाराणसी मंडल के अंतर्गत उनौला–पिपराइच रेलखंड के बीच पैच डबलिंग कार्य, प्री-नॉन इंटरलॉकिंग (Pre-NI) तथा नॉन इंटरलॉकिंग (NI) कार्य किया जाएगा। इस कार्य के कारण पश्चिम रेलवे द्वारा संचालित गाड़ी संख्या 19269/19270 पोरबंदर–मुजफ्फरपुर–पोरबंदर एक्सप्रेस कुछ निर्धारित तिथियों में परिवर्तित मार्ग से संचालित की जाएगी।

वरिष्ठ मंडल वाणिज्य प्रबंधक श्री अतुल कुमार त्रिपाठी ने जानकारी देते हुए बताया कि गाड़ी संख्या 19269 पोरबंदर - मुजफ्फरपुर एक्सप्रेस दिनांक 5 जून, 2026 को अपने निर्धारित मार्ग गोरखपुर–पनियहवा–नरकटियागंज–मुजफ्फरपुर के स्थान पर गोरखपुर–भटनी–छपरा ग्रामीण–मुजफ्फरपुर मार्ग से संचालित होगी।

इस दौरान यह गाड़ी निम्न स्टेशनों पर नहीं रुकेगीः सिसवा बाजार, बगहा, नरकटियागंज, बेतिया, सुगौली, बापूधाम मोतिहारी, चकिया तथा मेहसी।

गाड़ी संख्या 19270 मुजफ्फरपुर - पोरबंदर एक्सप्रेस दिनांक 24 मई, 31 मई, 1 जून, 7 जून एवं 8 जून, 2026 को अपने निर्धारित मार्ग मुजफ्फरपुर–नरकटियागंज–पनियहवा–गोरखपुर के स्थान पर मुजफ्फरपुर–छपरा ग्रामीण–भटनी–गोरखपुर मार्ग से संचालित होगी।

इस दौरान यह गाड़ी निम्न स्टेशनों पर नहीं रुकेगीः मेहसी, चकिया, बापूधाम मोतिहारी, सुगौली, बेतिया, नरकटियागंज, बगहा तथा सिसवा बाजार।

रेल प्रशासन यात्रियों से अनुरोध करता है कि यात्रा प्रारंभ करने से पूर्व अपनी गाड़ी की अद्यतन जानकारी के लिए NTES (National Train Enquiry System) अथवा वेबसाइट www.enquiry.indianrail.gov.in का उपयोग करें।

प्रधानमंत्री रोजगार मेले के अंतर्गत 23 मई, 2026 को सरकारी विभागों और संगठनों में नवनियुक्त युवाओं को 51,000 से अधिक नियुक्ति पत्र वितरित करेंगे

रोज़गार मेलों के माध्यम से अब तक 11.50 लाख से अधिक नियुक्ति पत्र किए जारी

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी 23 मई, 2026 को सुबह 11.00 बजे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से रेलवे सहित विभिन्न सरकारी विभागों और संगठनों में नवनियुक्त 51,000 से अधिक युवाओं को नियुक्ति पत्र वितरित करेंगे। इस अवसर पर वे नियुक्त लोगों को संबोधित भी करेंगे।

यह 19 वां रोज़गार मेला देशभर के 47 स्थलों पर आयोजित किया जाएगा। ये नियुक्तियां केंद्र सरकार के विभिन्न मंत्रालयों और विभागों में हो रही हैं। देश भर से चुने गए नए कर्मचारी रेल मंत्रालय, संचार मंत्रालय (डाक विभाग), रक्षा मंत्रालय, वित्तीय मंत्रालय सहित अन्य विभागों और मंत्रालयों के शामिल होंगे।

रोज़गार मेला, रोज़गार सृजन को सर्वोच्च प्राथमिकता देने की प्रधानमंत्री की प्रतिबद्धता को पूरा करने की दिशा में एक पहल है। रोज़गार मेला युवाओं को सशक्त बनाने और राष्ट्र निर्माण में उनकी भागीदारी के लिए सार्थक अवसर प्रदान करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। देश भर में रोज़गार मेलों के माध्यम से अब तक 11.50 लाख से अधिक नियुक्ति पत्र जारी किए जा चुके हैं।

इस अवसर पर पश्चिम रेलवे अहमदाबाद मण्डल में भी रोजगार मेला का आयोजन किया जा रहा है। इसके तहत कुल 115 नवीन चयनित अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र बांटे जाएंगे जिसमें रेलवे के 66, वित्तीय सेवा विभाग के 39, पोस्ट ऑफिस के 09, रक्षा मंत्रालय का 01 अभ्यर्थी भी शामिल हैं।

अहमदाबाद में आयोजित रोजगार मेला कार्यक्रम में माननीय केंद्रीय राज्यमंत्री युवा मामले और खेल मंत्रालय, श्रीमती रक्षा निखिल खडसे, माननीया राज्यमंत्री शहरी विकास और शहरी आवास, गुजरात श्रीमती दर्शनाबेन वाघेला, माननीय सांसद श्री दिनेशभाई मकवाणा, माननीय सांसद श्री हंसमुखभाई पटेल, माननीय सांसद (राज्यसभा) श्री नरहरि अमीन, माननीय विधायक श्री दिनेशसिंह कुशवाह सहित अन्य अतिथिगण समारोह में उपस्थित रहेंगे।

वडनगर में एलएंडटी की देश की सबसे बड़ी आईटीआई कार्यरत, रोजगार के सुनहरे अवसर

▸▸ एलएंडटी ने वडनगर में विश्व स्तरीय प्रशिक्षण सुविधाओं के साथ स्थापित किया है इंडस्ट्रियल कंस्ट्रक्शन स्किल्स ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट : दो पायलट बैच के कुल 201 छात्रों का प्रशिक्षण हुआ पूर्ण

▸▸ प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के स्किल इंडिया मिशन के विजन को आगे बढ़ाता है वडनगर का यह प्रशिक्षण संस्थान

▸▸ मुख्यमंत्री श्री भूपेंद्र पटेल के नेतृत्व में गुजरात सरकार पूरे राज्य में स्किल डेवलपमेंट सेंटरों की स्थापना के जरिए युवाओं को कौशल विकास के अवसर प्रदान करने को लगातार प्रयासरत है

▸▸ संस्थान का उद्देश्य लाखों युवाओं को उद्योग-उन्मुख कौशल से लैस करके रोजगार और उद्यमिता को प्रोत्साहन देना है

▸▸ वडनगर में 45 से 90 दिनों का प्रशिक्षण प्राप्त करने वाले युवा अभी सेमीकंडक्टर फैब उद्योग (धोलेरा), अहमदाबाद-मुंबई बुलेट ट्रेन, अहमदाबाद मेट्रो प्रोजेक्ट, खंभालिया स्थित सोलर पावर प्लांट और पानीपत रिफाइनरी प्रोजेक्ट जैसी बड़ी परियोजनाओं में 18 से 20 रुपए के स्टाइपेंड पर काम कर रहे हैं

▸▸ खास बात यह है कि, वडनगर के इस संस्थान में लड़के और लड़कियों दोनों के लिए रहने-खाने की व्यवस्था है, प्रशिक्षुओं से नहीं ली जाती है किसी प्रकार की फीस

गांधीनगर : प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी की जन्मभूमि वडनगर में प्रवेश करते समय विसनगर-वडनगर रोड के किनारे बिना बिजली के तार वाले तीन विशाल ट्रांसमिशन टावर हर किसी का ध्यान खींचते हैं। यह तीन ट्रांसमिशन टावर वास्तव में लार्सन एंड टूब्रो (एलएंडटी) कंपनी द्वारा मेहसाणा जिले के वडनगर में स्थापित इंडस्ट्रियल कंस्ट्रक्शन स्किल्स ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट (आईसीएसटीआई) द्वारा प्रशिक्षण देने के लिए लगाए गए 'प्रैक्टिकल मॉडल' हैं। प्रशिक्षु छात्र इन टावरों को लगाने (खड़ा करने) और उन्हें हटाने (खोलने) का प्रैक्टिकल अनुभव प्राप्त करते हैं।

30 बीघा क्षेत्र में फैले कैम्पस में इसी प्रकार की प्रायोगिक प्रशिक्षण की सुविधाएं देखने को मिलती हैं, जहां प्रशिक्षुओं को उद्योग-उन्मुख कार्यों के संबंध में प्रैक्टिकल प्रशिक्षण दिया जाता है।

एलएंडटी कंपनी ने गुजरात सरकार के सहयोग से वडनगर में विश्व स्तरीय प्रशिक्षण सुविधाओं के साथ इंडस्ट्रियल कंस्ट्रक्शन स्किल्स ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट (आईसीएसटीआई) स्थापित किया है। अब तक दो पायलट बैच के कुल 201 छात्रों का प्रशिक्षण पूर्ण हो चुका है और प्रशिक्षण पूरा होने के बाद सभी इच्छुक युवा 18 से 20,000 रुपए के मासिक स्टाइपेंड पर एलएंडटी कंपनी की विभिन्न परियोजनाओं पर कार्य कर रहे हैं।

खास बात यह है कि, यहां लड़के और लड़कियों, दोनों के लिए प्रशिक्षण की व्यवस्था की गई है। प्रशिक्षुओं से कोई फीस नहीं ली जाती है, और रहने-खाने की सुविधा भी बिल्कुल मुफ्त दी जाती है।

वडनगर निवासी और कॉमर्स ग्रेजुएट रोनल कड़िया को दो महीने पहले इस स्किल ट्रेनिंग सेंटर के बारे में जानकारी मिली। उन्होंने यहां फॉर्मवर्क कारपेंटरी विभाग में प्रवेश लिया। प्रशिक्षण पूरा होने के बाद उन्हें कंपनी ने उन्हें तुरंत ही स्टाइपेंड पर काम पर रख लिया गया। अभी रोनक कड़िया अहमदाबाद-मुंबई बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट पर मेहमदाबाद में काम कर रहे हैं। लार्सन एंड टूब्रो (एलएंडटी) कंपनी भारत की सबसे बड़ी और अग्रणी इंजीनियरिंग एवं कंस्ट्रक्शन कंपनी है, जो दुनिया भर में विशाल और जटिल परियोजनाओं का निर्माण करती है।

रोनल कड़िया ने कहा, "मुझे आईसीएसटीआई-वडनगर में काफी कुछ सीखने को मिला और मेरा कौशल भी बढ़ा। अभी मैं बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट की मेहमदाबाद साइट पर काम करता हूं। अपने अनुभव के बाद, मैंने अपने मित्रों से भी इस संस्थान से प्रशिक्षण प्राप्त करने को कहता हूं, क्योंकि इस संस्थान में उत्तम प्रशिक्षण दिया जाता है और नौकरी की सुनहरी संभावनाएं हैं।"

पिछले तीन महीनों में यहां से विभिन्न ट्रेड 201 युवाओं ने प्रशिक्षण पूरा कर लिया है। प्रशिक्षित युवा अभी सेमीकंडक्टर फैब उद्योग (धोलेरा), बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट, मेट्रो रेल प्रोजेक्ट (अहमदाबाद), सोलर पावर प्लांट (खंभालिया) और पानीपत रिफाइनरी प्रोजेक्ट (हरियाणा) जैसे एलएंडटी के बड़े प्रोजेक्ट में 18 से 20,000 रुपए के मासिक स्टाइपेंड के साथ काम कर रहे हैं।

आईसीएसटीआई-वडनगर में कंस्ट्रक्शन, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर और नए उद्योगों के विषय में प्रशिक्षण दिया जाता है। उद्योग की मांग और कौशल की जरूरत के मुताबिक 45, 60 या 90 दिनों के कोर्स चलाए जाते हैं। इस संस्थान में 20 से अधिक ट्रेड में प्रशिक्षण दिया जाता है, जो देश भर में एलएंडटी द्वारा संचालित सभी स्किल ट्रेनिंग सेंटरों में सबसे अधिक है।

एलएंडटी सीएसटीआई-वडनगर के प्रमुख निरंजन मिश्रा ने कहा, "एलएंडटी का स्किल ट्रेनिंग फ्रेमवर्क यूके के कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री ट्रेनिंग बोर्ड (सीआईटीबी) के मानदंडों पर आधारित है। कंस्ट्रक्शन स्किल्स ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट (सीएसटीआई) ने सीआईटीबी के मार्गदर्शन में पाठ्यक्रम तैयार किया है, इसलिए यहां प्रशिक्षण का स्तर वैश्विक मानदंडों के अनुरूप है।"

एलएंडटी सीएसटीआई-वडनगर के प्रमुख निरंजन मिश्रा ने आगे कहा, "आईसीएसटीआई प्रशिक्षित वर्करों को उनकी ट्रेड स्किल्स के आधार पर लेवल-2, लेवल-3 या लेवल-4 में वर्गीकृत करता है। प्रशिक्षण पूरा होने के बाद उम्मीदवारों को एलएंडटी की बड़ी कंस्ट्रक्शन और हाइड्रोकार्बन परियोजनाओं में नेशनल अप्रेंटिसशिप प्रमोशन स्कीम (एनएपीएस) के तहत 24 महीने और प्रधानमंत्री इंटर्नशिप स्कीम (पीएमआईएस) के अंतर्गत 9 महीने के लिए शामिल किया जाता है, यानी उन्हें कुल 33 महीने के लिए स्टाइपेंड के साथ रोजगार का अवसर मिलता है।"

निरंजन मिश्रा ने नौकरी के सुनहरे अवसरों पर प्रकाश डालते हुए बताया, "एनएपीएस कार्यक्रम के अंतर्गत दो वर्ष सफलतापूर्वक पूर्ण होने के बाद उम्मीदवार फ्रंट लाइन सुपरवाइजर (एफएलएस) के पद के लिए पात्र बन जाते हैं। साथ ही, दो वर्ष के बाद अंतरराष्ट्रीय प्लेसमेंट का मौका भी दिया जाता है।"

वडनगर स्थित यह नया प्रशिक्षण संस्थान प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के स्किल इंडिया मिशन के विजन को आगे बढ़ाता है। यह संस्थान लाखों युवाओं को उद्योग-उन्मुख कौशल प्रदान कर रोजगार और उद्यमिता को बढ़ावा देता है।

मुख्यमंत्री श्री भूपेंद्र पटेल के नेतृत्व में गुजरात सरकार उद्योगों के साथ भागीदारी करके और राज्य भर में स्किल डेवलपमेंट सेंटरों की स्थापना के जरिए युवाओं में उद्योग-उन्मुख नए कौशल विकसित करने की दिशा में निरंतर प्रयासरत है।

वडनगर स्थित संस्थान में इन व्यवसायों का दिया जाता है प्रशिक्षण

वडनगर स्थित आईसीएसटीआई में कुल 20 से अधिक ट्रेड में प्रशिक्षण दिया जाता है, जिनमें फॉर्मवर्क-कारपेंटरी, बार बैंडिंग और स्टील फिक्सिंग, स्कैफोल्डिंग, प्री-स्ट्रेसिंग, मेसनरी, प्लास्टरिंग, टाइलिंग, वेट पार्टिशन, प्लम्बिंग और सैनिटरी, इलेक्ट्रिशियन, कंक्रीट लेबोरेटरी और फील्ड टेस्टिंग, सर्वेइंग, वेल्डिंग, पाइप फिटिंग, एचवीएसी, फायर फाइटिंग, प्लांट एंड मशीनरी (पीएंडएम), ऑपरेशंस एंड मेंटेनेंस (डब्ल्यूईटी), सोलर ट्रांसमिशन टावर इरेक्शन, ईएलवी टेलीकम्युनिकेशन, सोलर पीवी टेक्नीशियन, सीसीटीवी, एफएलएस, ईएचएस, आईओटी और टीओटी जैसे कई पाठ्यक्रम शामिल हैं।

प्रशिक्षण सहित रहने-खाने की सारी सुविधाएं बिल्कुल मुफ्त

प्रशिक्षुओं को किसी भी प्रकार की फीस जमा करने की जरूरत नहीं है और रहने-खाने की सुविधाएं भी एलएंडटी की ओर से पूरी तरह से मुफ्त में दी जाती हैं। पुरुषों और महिलाओं के लिए अलग-अलग छात्रावास की व्यवस्था, स्टाफ के लिए रहने की व्यवस्था, डाइनिंग और किचन सुविधा, खेल मैदान, ध्यान और योग हॉल, जिम, हेल्थकेयर, टीवी रूम और इंडोर गेम्स जैसी मनोरंजन की सुविधाएं भी परिसर में उपलब्ध हैं।

यहां प्रशिक्षुओं को ओपन यार्ड, वर्कशॉप में विश्व स्तरीय स्किल डिजाइन तथा स्पेसिफिकेशन के साथ आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ ट्रेनिंग दी जाती है। इसके अलावा, कंक्रीट और स्टील एलिमेंट्स की 'रेडी टू बिल्ड' फैक्ट्री में प्रैक्टिकल अनुभव भी दिया जाता है।"

केवल आठ महीने में तैयार हो गया संस्थान

राज्य सरकार ने युवाओं का कौशल बढ़ाने के लिए एलएंडटी को कुछ ही दिनों के भीतर जमीन आवंटित कर दी थी। जमीन मिलने के केवल आठ महीने के भीतर ही कंपनी ने राज्य सरकार के सहयोग से इस परिसर में सभी व्यवस्थाएं खड़ी कर संस्थान को कार्यरत कर दिया।

एलएंडटी ने वडनगर में स्किल्स ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट विकसित करने के लिए 10 मार्च, 2025 को अपने कॉर्पोरेट-सामाजिक दायित्व (सीएसआर) विभाग के जरिए गुजरात सरकार के साथ एक समझौता ज्ञापन (एमओयू) पर हस्ताक्षर किए थे। यह संस्थान 17 सितंबर, 2025 को 201 छात्रों के साथ संचालित हुआ। संयोग से, इसी दिन (17 सितंबर) प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी का 75वां जन्मदिन भी था।

किसे मिल सकता है प्रवेश?

18 से 35 वर्ष की उम्र का कोई भी उम्मीदवार इन पाठ्यक्रमों में प्रवेश ले सकता है। शैक्षणिक योग्यता ट्रेड के अनुसार निर्धारित होती है। सिविल ट्रेड कोर्स के लिए कक्षा 5 पास उम्मीदवार भी प्रवेश ले सकते हैं, जबकि अन्य कोर्स के लिए आईटीआई पास होना अनिवार्य है।

यदि कोई इस संस्थान में प्रशिक्षण प्राप्त करना चाहता है, तो संस्थान के इन नंबरों पर संपर्क कर सकता है : 7043568437, 9099903673, 7016813062

मानसून से पहले सूरत में जर्जर इमारतों के खिलाफ कार्रवाई की जरूरत है, आम जनता के जीवन को खतरे में डालने की आशंका जताई जा रही है

(छगनलाल मेवाड़ा द्वारा) सूरत। शहर में तापमान बढ़ रहा है। नागरिक पसीने से तरबतर हैं। फिर एक महीने में मानसून का मौसम शुरू हो जाएगा। उस समय हमें बात करनी होगी। शहर में बहुत सारी निजी और सरकारी इमारतें हैं। ऐसे में, खतरनाक हालत में मौजूद इमारतों के मालिकों को नोटिस देकर यूं ही बैठे रहने से कोई फायदा नहीं होगा।

आम जनता के जीवन को खतरे से बचाने के लिए ऐसे भवन मालिकों या ट्रस्टियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करना आवश्यक है। लगभग दो महीने पहले, करवा रोड पर स्थित एक जर्जर इमारत की तीसरी मंजिल सुबह 3:45 से 4:00 बजे के बीच अचानक गिर गई। सौभाग्य से वहां कोई मौजूद नहीं था, इसलिए कोई बड़ी दुर्घटना नहीं हुई। इसके बाद, एसएमसी द्वारा नोटिस भेजे जाने के बावजूद, ट्रस्टी संतुष्ट नहीं हुए और अंततः एसएमसी ने जर्जर इमारत को ध्वस्त कर दिया।

अब बात करते हैं इस तथ्य की कि राज्य में मानसून शुरू होने से पहले, सूरत नगर आयुक्त को शहरी विकास विभाग के माध्यम से शहर की सभी जर्जर संपत्तियों, चाहे वे सरकारी हों या निजी, का संपूर्ण सर्वेक्षण कराना चाहिए और मानसून शुरू होने से पहले ऐसी जर्जर संपत्तियों को हटवाना चाहिए। इससे आसपास की संपत्तियों को होने वाला खतरा कम हो जाएगा और मानसून के दौरान जान-माल का कोई नुकसान नहीं होगा।

इतना ही नहीं, यह आवश्यक है कि इस कार्य को क्षेत्रवार संचालित किया जाए और जर्जर मकानों, जर्जर दीवारों, जर्जर फ्लैटों सहित सभी खतरनाक संपत्तियों का सर्वेक्षण किया जाए, ऐसी संपत्तियों की सूची बनाई जाए और निवासियों को यथाशीघ्र इन संपत्तियों को खाली करने की चेतावनी दी जाए। इसके साथ ही, मानसून की शुरुआत में इन संपत्ति मालिकों को स्वेच्छा से जर्जर संपत्तियों को खाली करने के सख्त निर्देश देना आवश्यक है। अतीत में भी, मानसून के दौरान शहर के विभिन्न क्षेत्रों में पुरानी जर्जर संपत्तियों के कुछ हिस्सों के ढहने की खबरें प्रतिदिन समाचार पत्रों में छपती रही हैं। इसलिए, जनहित में, हम सूरत नगर निगम के नगर आयुक्त और शहरी विकास विभाग के क्षेत्र प्रमुखों से इस मामले पर ध्यान देने और यथाशीघ्र खतरनाक संपत्तियों को खाली कराने की अपील करते हैं।

अब यह देखना बाकी है कि सूरत नगर निगम के नए महापौर, उप महापौर और स्थायी समिति के अध्यक्ष ऐसे गंभीर मामलों को कितनी गंभीरता से लेंगे और जनता के हितों को कितनी प्राथमिकता देंगे।

बलात्कार के आरोपी के रोड शो के बाद सवाल उठे, महिलाओं की सुरक्षा पर बहस फिर से तेज हो गई

(छगनलाल मेवाड़ा द्वारा) सूरत। यह देश अब किस दिशा में जा रहा है? यह कहना और भी मुश्किल है। क्योंकि एक तरफ तो महिलाओं की सुरक्षा, आरक्षण और हिफाज़त की बातें हवा भरे गुब्बारों की तरह हो रही हैं, वहीं दूसरी तरफ हिंदू युवा वाहिनी के पूर्व सदस्य सुशील प्रजापति, जिन पर कानून की छात्रा से बलात्कार का आरोप है, उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद की जेल से जमानत पर रिहा होने के बाद फूलों की मालाओं से उनका स्वागत किया गया। आरोपी के इस तरह के स्वागत का वीडियो भी बनाया गया। जमानत पर रिहा होते ही बलात्कार के आरोपी ने सफेद कपड़े पहनकर और ज्वार की माला ओढ़कर सड़क पर प्रदर्शन किया। इससे लोगों में आक्रोश फैल गया।

वीडियो में, उनके समर्थक उन्हें अपने कंधों पर उठाए हुए, नारे लगाते हुए और विजय रैली की तरह मार्च करते हुए, हाथ मिलाते और मुस्कुराते हुए दिखाई दे रहे हैं, जबकि आरोपी "वी" का चिन्ह बनाते हुए दिखाई दे रहे हैं, वहीं अन्य लोग अपने मोबाइल फोन हवा में लहराते हुए, चल रही घटनाओं को रिकॉर्ड करने की कोशिश करते हुए दिखाई दे रहे हैं।

आरोपी पर एक विधि छात्रा को वकील से मिलवाने के बहाने फ्लैट में ले जाकर उसके साथ बलात्कार करने का आरोप है। लगभग नौ महीने बाद, आरोपी को 17 मई को जमानत पर रिहा कर दिया गया। इस घटना के संबंध में पुलिस का कहना है कि वे वायरल वीडियो की जांच कर रहे हैं जिसमें समर्थक आरोपी पर फूल बरसाते और वाहनों के काफिले में शामिल होते दिख रहे हैं। अब देखना यह होगा कि पुलिस ऐसे आरोपी को कानून का क्या सबक सिखाती है और उसे उसके उचित स्थान पर कैसे लाती है?

कच्छ से देश की राजधानी का सफर हुआ आसान: भुज और दिल्ली के बीच नई दैनिक एक्सप्रेस ट्रेन सेवा का शुभारंभ

माननीय रेल मंत्री श्री अश्विनी वैष्णव एवं गुजरात के माननीय मुख्यमंत्री श्री भूपेन्द्र पटेल वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से दिखाएंगे हरी झंडी

रेल यात्रियों की सुविधा को सर्वोपरि रखते हुए तथा कच्छ क्षेत्र को राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली से सीधे और बेहतर रेल संपर्क प्रदान करने के उद्देश्य से रेल मंत्रालय एक ऐतिहासिक कदम उठाने जा रहा है। दिनांक 22 मई 2026 को भुज और दिल्ली के बीच नई दैनिक ट्रेन सेवा का शुभारंभ किया जाएगा। यह रेलगाड़ी पश्चिम रेलवे के भुज स्टेशन एवं दिल्ली के बीच प्रतिदिन संचालित की जाएगी तथा गुजरात, राजस्थान एवं हरियाणा के विभिन्न महत्वपूर्ण स्टेशनों को जोड़ेगी।

इस नई ट्रेन सेवा को माननीय रेल मंत्री श्री अश्विनी वैष्णव एवं गुजरात के माननीय मुख्यमंत्री श्री भूपेन्द्र पटेल वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से हरी झंडी दिखाकर रवाना करेंगे। इस ऐतिहासिक अवसर पर भुज स्टेशन पर आयोजित कार्यक्रम में माननीय सांसद (कच्छ) श्री विनोद एल. चावड़ा, माननीय विधायक (भुज) श्री केशुभाई शिवदास पटेल सहित महाप्रबंधक पश्चिम रेलवे श्री रामाश्रय पाण्डेय, मण्डल रेल प्रबंधक अहमदाबाद श्री वेद प्रकाश सहित अन्य वरिष्ठ अधिकारी और गणमान्य अतिथि व्यक्तिगत रूप से उपस्थित रहेंगे।

उद्घाटक ट्रेनः सेवा गाड़ी संख्या 09403 भुज–दिल्ली उद्घाटक स्पेशल

गाड़ी संख्या 09403 भुज–दिल्ली उद्घाटक स्पेशल 22 मई 2026 को भुज से 16.30 बजे प्रस्थान करेगी तथा अगले दिन 16.30 बजे दिल्ली पहुंचेगी।

मार्ग में यह ट्रेन अंजार, गांधीधाम, भचाऊ, भीलड़ी, धानेरा, रानीवाड़ा, मारवाड़ भीनमाल, मोदरान, जालोर, मोकलसर, समदड़ी, लूणी, पाली मारवाड़, मारवाड़ जंक्शन, ब्यावर, अजमेर, किशनगढ़, जयपुर, गांधी नगर-जयपुर, बांदीकुई, अलवर एवं रेवाड़ी स्टेशनों पर ठहरेगी।

इस ट्रेन में 2-टियर एसी, 3-टियर एसी, स्लीपर तथा सामान्य श्रेणी के कोच रहेंगे।

यात्रियों को होगा विशेष लाभ

▸▸ कच्छ और दिल्ली के बीच सीधा संपर्कः अब कच्छ वासियों को देश की राजधानी दिल्ली जाने के लिए ट्रेनों को बदलने की आवश्यकता नहीं होगी। यह दैनिक सेवा समय की बचत करेगी।

▸▸ व्यापार और उद्योग को गतिः कच्छ का दिन 11:45 बजे दिल्ली पहुंचेगी। इसी प्रकार, गाड़ी संख्या 19404 दिल्ली–भुज एक्सप्रेस 24 मई 2026 से प्रतिदिन दिल्ली से 16:40 बजे प्रस्थान करेगी तथा अगले दिन 19:35 बजे भुज पहुंचेगी।

मार्ग में प्रमुख ठहराव

यह ट्रेन मार्ग में दोनों दिशाओं में अंजार, गांधीधाम, भचाऊ, भीलड़ी, धानेरा, रानीवाड़ा, मारवाड़ भीनमाल, मोदरान, जालोर, मोकलसर, समदड़ी, लूणी, पाली मारवाड़, मारवाड़ जंक्शन, ब्यावर, अजमेर, किशनगढ़, जयपुर, गांधी नगर-जयपुर, बांदीकुई, अलवर एवं रेवाड़ी स्टेशनों पर ठहरेगी।

हस्तशिल्प, कपड़ा उद्योग और गांधीधाम-भुज क्षेत्र के उद्योगों को दिल्ली, जयपुर और अजमेर जैसे बड़े बाजारों से सीधा जुड़ाव मिलेगा, जिससे स्थानीय व्यापार को भारी बढ़ावा मिलेगा।

▸▸ पर्यटन में भारी उछालः 'रण उत्सव' और कच्छ के सांस्कृतिक वैभव को देखने आने वाले देश-विदेश के पर्यटकों के लिए अब दिल्ली से सीधी कनेक्टिविटी उपलब्ध होगी, जिससे क्षेत्र में पर्यटन रोजगार बढ़ेगा।

▸▸ विद्यार्थियों और मरीजों के लिए वरदानः उच्च शिक्षा के लिए दिल्ली-जयपुर जाने वाले छात्रों और बेहतर चिकित्सा सुविधाओं के लिए यात्रा करने वाले मरीजों को इस दैनिक और आरामदायक ट्रेन सेवा से बेहद सहूलियत होगी।

▸▸ धार्मिक पर्यटन को बढ़ावाः अजमेर शरीफ, जयपुर और राजस्थान के अन्य धार्मिक स्थलों की यात्रा करने वाले श्रद्धालुओं के लिए यह ट्रेन एक सुलभ और किफायती माध्यम बनेगी।

'मेलोडी टॉफी' को मिला ग्लोबल बूस्ट मोदी-मेलोनी मुलाकात के बाद बढ़ी डिमांड

नई दिल्ली। प्रधानमंत्री Narendra Modi द्वारा इटली की प्रधानमंत्री Giorgia Meloni को 'मेलोडी टॉफी' भेंट किए जाने का वीडियो सामने आने के बाद देश में इस ब्रांड की लोकप्रियता अचानक तेजी से बढ़ गई है। सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल होते ही बाजार में इस टॉफी की मांग में तेज उछाल देखा गया, जिसके बाद कंपनी Parle Products ने उत्पादन बढ़ाने का फैसला लिया है।

कंपनी के अधिकारियों के मुताबिक, जैसे ही यह वीडियो इंटरनेट पर वायरल हुआ, देशभर में वितरकों और ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म्स पर 'मेलोडी' टॉफी की बिक्री में उल्लेखनीय बढ़ोतरी दर्ज की गई। उपभोक्ताओं की बढ़ती मांग ने कंपनी को उत्पादन लाइन बढ़ाने और सप्लाई चेन को तेज करने के लिए मजबूर कर दिया है।

पार्ले प्रोडक्ट्स के उपाध्यक्ष मयंक शाह ने कहा कि यह पहली बार है जब किसी वायरल सार्वजनिक घटना के बाद किसी उत्पाद की मांग इतनी तेजी से बढ़ी है। उनके अनुसार, यह ब्रांड के इतिहास का अब तक का सबसे बड़ा अप्रत्याशित

प्रचार अभियान बन गया है। उन्होंने यह भी बताया कि कंपनी अब इस बढ़ती मांग को संभालने के लिए उत्पादन क्षमता को तत्काल बढ़ा रही है।

कंपनी का कहना है कि 'मेलोडी' टॉफी पहले से ही अंतरराष्ट्रीय स्तर पर मौजूद है और यह 100 से अधिक देशों में उपलब्ध है। लेकिन हालिया घटनाक्रम के बाद इस ब्रांड को नई वैश्विक पहचान मिल रही है। कंपनी अब इसे अंतरराष्ट्रीय बाजारों में और अधिक मजबूत करने की रणनीति पर काम कर रही है।

सूत्रों के अनुसार, वीडियो वायरल होने के बाद क्विक कॉमर्स और ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म्स पर "मेलोडी टॉफी" की खोज में भी अचानक भारी वृद्धि दर्ज की गई। कई ऑनलाइन स्टोर्स पर स्टॉक तेजी से खत्म होने की स्थिति बन गई, जिसके चलते कंपनी को सप्लाई को स्थिर करने के लिए तत्काल कदम उठाने पड़े।

सोशल मीडिया पर इस टॉफी को लेकर तरह-तरह की प्रतिक्रियाएं देखने को मिल रही हैं। कुछ लोग इसे एक हल्का-फुल्का और मजेदार पल बता रहे हैं, जबकि कुछ इसे स्वदेशी ब्रांड की वैश्विक ब्रांडिंग के रूप में देख रहे हैं।

विशेषज्ञों का मानना है कि यह घटना इस बात का उदाहरण है कि आज के डिजिटल युग में एक छोटा सा सार्वजनिक क्षण भी किसी ब्रांड की किस्मत बदल सकता है। जब कोई उत्पाद किसी बड़े राजनीतिक या अंतरराष्ट्रीय मंच पर दिखाई देता है, तो उसका प्रभाव सीधे उपभोक्ता व्यवहार पर पड़ता है।

Parle Products अब इस मौके का इस्तेमाल अपने अन्य उत्पादों की तरह 'मेलोडी' ब्रांड को भी मजबूत करने में कर रही है। कंपनी ने डिजिटल मार्केटिंग अभियान तेज कर दिया है और विभिन्न प्लेटफॉर्म्स पर प्रमोशन भी शुरू कर दिया है।

फिलहाल बाजार में इस टॉफी को लेकर उत्साह का माहौल बना हुआ है और कंपनी को उम्मीद है कि आने वाले दिनों में इसकी मांग और बढ़ सकती है। यह घटना एक बार फिर साबित करती है कि ब्रांडिंग और लोकप्रियता का नया दौर अब सोशल मीडिया और वैश्विक घटनाओं से तय हो रहा है।

जयपुर की सड़कों पर बढ़ता मौत का साया, चार महीने में 293 जानें गईं, तीन साल का रिकॉर्ड टूटा

जयपुर। राजधानी जयपुर में सड़क सुरक्षा को लेकर हालात लगातार चिंताजनक होते जा रहे हैं। वर्ष 2026 के शुरुआती चार महीनों में सामने आए आंकड़ों ने पिछले तीन वर्षों के सभी रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। Jaipur की सड़कों पर जनवरी से अप्रैल 2026 के बीच 293 लोगों की दर्दनाक मौत हो चुकी है, जबकि 960 से अधिक लोग गंभीर रूप से घायल होकर अस्पतालों में जिंदगी और मौत के बीच संघर्ष कर रहे हैं। इन आंकड़ों ने शहर की परिवहन व्यवस्था और यातायात अनुशासन पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। आंकड़ों के अनुसार, इस अवधि में कुल 1133 सड़क हादसे दर्ज किए गए हैं। इसका मतलब यह है कि औसतन हर दिन तीन लोगों की जान सड़क दुर्घटनाओं में जा रही है। यह स्थिति न केवल प्रशासन के लिए चुनौती है, बल्कि आम जनता की लापरवाही और यातायात नियमों की अनदेखी का भी बड़ा परिणाम है। पुलिस अधिकारियों के मुताबिक, अधिकांश हादसे तेज गति, नशे में वाहन चलाने, हेलमेट और सीट बेल्ट के उपयोग में लापरवाही तथा गलत ओवरटेकिंग जैसे कारणों से हो रहे हैं।

जयपुर में लगातार बढ़ते वाहन दबाव ने स्थिति को और गंभीर बना दिया है। शहर में 35 लाख से अधिक पंजीकृत वाहन सड़क पर दौड़ रहे हैं, जबकि ट्रैफिक अनुशासन और ड्राइविंग स्किल्स में कमी हादसों की बड़ी वजह बन रही है। भीड़भाड़ वाले चौराहों, अनियंत्रित ट्रैफिक और कई जगहों पर अव्यवस्थित सड़क संरचना भी दुर्घटनाओं को बढ़ावा दे रही है।

जोनवार आंकड़ों पर नजर डालें तो स्थिति और भी चिंताजनक दिखाई देती है। जयपुर पूर्व में 382 हादसों में 91 मौतें और 309 घायल दर्ज किए गए हैं। जयपुर पश्चिम में 351 हादसों में 102 लोगों की जान गई और 307 लोग घायल हुए। जयपुर उत्तर में 76 हादसों में 17 मौतें और 64 घायल हुए, जबकि जयपुर दक्षिण में 324 दुर्घटनाओं में 83 लोगों की मौत और 280 लोग घायल हुए।

अगर पिछले वर्षों से तुलना की जाए तो तस्वीर और स्पष्ट हो जाती है। वर्ष 2025 के पहले चार महीनों में 1059 हादसों में 275 मौतें और 944 घायल दर्ज किए गए थे। वहीं वर्ष 2024 में इसी अवधि में 1051 सड़क हादसों में 279 लोगों की जान गई और 882 लोग घायल हुए थे। इन आंकड़ों से साफ है कि 2026 में सड़क दुर्घटनाओं की गंभीरता और बढ़ गई है।

वर्ष 2025 के आंकड़ों में जयपुर पश्चिम में 104 मौतें दर्ज की गई थीं, जो उस समय सबसे अधिक थीं। वहीं 2024 में भी स्थिति चिंताजनक रही थी, जब कुल 279 लोगों की मौत हुई थी। लेकिन 2026 में यह संख्या पहले ही चार महीनों में 293 तक पहुंच चुकी है, जो पिछले वर्षों की तुलना में अधिक भयावह संकेत देती है। विशेषज्ञों का मानना है कि यह बढ़ोतरी केवल ट्रैफिक दबाव का परिणाम नहीं है, बल्कि यातायात नियमों के प्रति गंभीर लापरवाही भी इसका बड़ा कारण है। कई मामलों में बिना लाइसेंस वाहन चलाना, नाबालिगों द्वारा वाहन चलाना और ट्रैफिक नियमों की अनदेखी लगातार हादसों को बढ़ा रही है।

इस स्थिति को देखते हुए पुलिस प्रशासन अब पूरी तरह एक्शन मोड में नजर आ रहा है। एडिशनल कमिश्नर योगेश दाधीच ने बताया कि शहर में ब्लैक स्पॉट्स की पहचान की जा रही है और उन स्थानों पर सुधार कार्य तेजी से किया जा रहा है। कई जगहों पर अवैध कट्स को बंद किया जा रहा है ताकि दुर्घटनाओं को रोका जा सके। इसके अलावा शराब पीकर वाहन चलाने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जा रही है और बार-बार नियम तोड़ने वालों के ड्राइविंग लाइसेंस रद्द करने की प्रक्रिया भी शुरू कर दी गई है। पुलिस का कहना है कि अब लापरवाही करने वालों के खिलाफ किसी तरह की नरमी नहीं बरती जाएगी।

हालांकि प्रशासनिक प्रयासों के बावजूद स्थिति में तुरंत सुधार की उम्मीद आसान नहीं दिखती, क्योंकि शहर में वाहनों की संख्या लगातार बढ़ रही है और सड़क अनुशासन अपेक्षाकृत कमजोर बना हुआ है। विशेषज्ञों का मानना है कि जब तक नागरिक स्तर पर जागरूकता और जिम्मेदारी नहीं बढ़ेगी, तब तक केवल प्रशासनिक कार्रवाई से समस्या का स्थायी समाधान मुश्किल है।

जयपुर की यह स्थिति न केवल एक शहर की ट्रैफिक समस्या है, बल्कि यह पूरे देश के शहरी यातायात प्रबंधन के लिए एक चेतावनी भी है कि बढ़ते वाहन और घटती अनुशासन व्यवस्था मिलकर किस तरह जीवन के लिए खतरा बन सकते हैं।